मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, गुरुवार 01 अक्टूबर 2026 | वर्ष-07, अंक-334, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

नई कृषि तकनीक करेगी किसानों को लाभान्वित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उमरिया को जल्द ही मिलेगी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की सौगात

एक सत बुलेटिन, भोपाल



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के साथ अनेक जनहितैषी निर्णय लिए हैं। किसानों को नई तकनीक का लाभ दिया जा रहा है। उमरिया जिला कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे काला सोना भी कहते हैं। यहां स्थित बांधवगढ़ किला मध्यप्रदेश की शान है। उमरिया जिला प्राकृतिक औषधि और वन्यजीव संपदा से समृद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उमरिया जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिले के किसानों को उपज का समुचित मूल्य दिलवाने के लिए नई कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तम खेती के लिए सिंचाई सुविधाएं बेहद जरूरी है। इसीलिए राज्य सरकार ने हर गांव और हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान धान और श्रीअन्न फसलों के उपार्जन के लिए समय रहते पंजीयन कराएं, ताकि एमएसपी का लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि इसी सीजन से किसानों को दिन में भी 10 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को किसान चौपाल लगाकर हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान गोपालन, दूध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी फसलों और जैविक-प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं। उन्होंने उमरिया के किसानों को बताया कि शीघ्र ही जिले में एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होगी। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को पंचायत स्तर पर दुग्ध संकलन समितियों के पंजीयन कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कस्टम हायरिंग सेंटर और सोलर पंप जैसी कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा कार्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में सेवा से संकल्प अभियान जारी है। राज्य सरकार जिलों में जन विश्वास अभियान के जरिए भी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दे रही है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अभिलेखों की नि:शुल्क रजिस्ट्री करवाई जा रही है। किसानों को भी इस स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है। संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री मिलने से हितग्राही बैंक लोन और अन्य आवश्यकताओं के लिए इसे उपयोग कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षित और समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार स्कूली बच्चों को कई सौगातें दे रही है। शासकीय स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी दी गई हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को नि:शुल्क किताबें, ड्रेस और साइकिलें वितरित की जा रही हैं। प्रदेशभर में सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बलराम कृषि महोत्सव के लिए उमरिया में उपस्थित मंत्री श्री नागर सिंह चौहान और पूर्व मंत्री सुश्री मीना सिंह से भी संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय जन उपस्थित थे।

2-0 से जीती सीरीज

भारत ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया,



एजेन्सी, गुवाहाटी

टीम इंडिया ने अपने 52 साल के वनडे इतिहास में पहली बार 400 रन से ऊपर का टारगेट चेज कर लिया है। गुवाहाटी में बुधवार को खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 405 रन बनाए। जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से जीत ली।

कप्तान शुभमन गिल भारत की जीत के हीरो रहे। उन्होंने वनडे क्रिकेट की सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाई। गिल ने 117 गेंदों पर 200 रन का आंकड़ा पार किया। उन्होंने 133 बॉल पर नाबाद 223 रन बनाए। 26 चौके और 8 छक्के भी जमाए।

गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 255 रन की पार्टनरशिप की। रोहित ने 35 वां शतक लगाया। उन्होंने 101 रन बनाए। विराट कोहली 29 रन बनाकर आउट हुए। गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड 31 रन बनाकर नॉटआउट रहे।

गिल ने सबसे तेज डबल सेंचुरी जमाने के मामले में भारत के ही ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ईशान ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया था। यह गिल का दूसरा दोहरा शतक भी है। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 149 बॉल पर 208 रन बनाए थे।

भारत से पहले वनडे क्रिकेट में 400 रन से ज्यादा का टारगेट सिर्फ साउथ अफ्रीका ने चेज किया था। साउथ अफ्रीका ने 2006 में जोहानसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का टारगेट हासिल किया था।

भारत ने 1974 में खेला था पहला वनडे

भारत ने 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे खेला था। उसके बाद से अब तक भारत का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रन चेज 360 रन था। टीम ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड हासिल किया था।

वार सहकर बचाई 174 यात्रियों की जान

भारतीय पायलट ने विमान क्रैश होने से बचाया, चाकू मार रहे को-पायलट से लड़े

एजेन्सी, नई दिल्ली



दुबई से इस्त्राइल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में बुधवार को ऐसा संकट आया, जिसने 174 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। विमान को भारतीय कैप्टन स्मित मछार उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान कॉकपिट में भारतीय कैप्टन और ओमानी सह-पायलट के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान चाकू से हमला किया गया और विमान अचानक तेजी से नीचे आने लगा। सह-पायलट पर विमान को जानबूझकर गिराने की कोशिश का संदेह है। भारतीय कैप्टन मछार ने इस्त्राइली यात्रियों की मदद से उसे काबू किया और विमान को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट में सुरक्षित उतारा गया।

कॉकपिट में भारतीय कैप्टन पर हमला कैसे हुआ?

इस्त्राइली अधिकारियों के अनुसार, कॉकपिट में संघर्ष के दौरान ओमानी सह-पायलट पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने का संदेह है। इसी दौरान सह-पायलट और भारतीय कैप्टन के बीच संघर्ष हुआ। सह-पायलट को भी चाकू लगने की बात सामने आई है। आखिरकार भारतीय कैप्टन ने विमान में मौजूद इस्त्राइली यात्रियों की मदद से सह-पायलट को काबू किया। एक यात्री के अनुसार, कॉकपिट की तरफ से चीखने की आवाजें आईं और वहां काफी खून दिखाई दिया। विमान में मौजूद डॉक्टर और नर्स ने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया।

घटना के समय विमान में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। कॉकपिट में झड़प के बीच विमान की स्थिति अचानक गंभीर हो गई। विमान की ऊंचाई करीब 34 हजार फीट से तेजी से घटकर 14 हजार फीट तक पहुंच गई। फ्लाइट ट्रैकिंग के अनुसार, एक समय विमान के नीचे आने की रफ्तार करीब 30,976 फीट प्रति मिनट दर्ज हुई। इस दौरान भारतीय कैप्टन ने स्थिति संभाली और यात्रियों की मदद से सह-पायलट को काबू किया। इसके बाद विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़कर तबुक में उतारा गया।

विमान सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा। फ्लाईदुबई ने सभी यात्रियों के सुरक्षित होने और उनकी देखभाल किए जाने की बात कही।

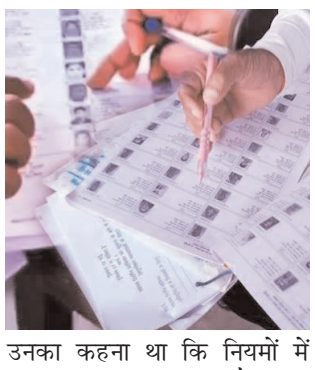
क्यों जारी हुआ हाईजैक का अलर्ट

फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 ने दुबई से सुबह 7:05 बजे उड़ान भरी थी और उसे करीब 9:30 बजे तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचना था। करीब 90 मिनट बाद विमान ने पहले 7700 आपातकालीन कोड भेजा। इसके बाद 7500 कोड प्रसारित हुआ, जो विमान में अवैध हस्तक्षेप और संभावित हाईजैक से जुड़ा होता है। विमान ने रास्ता बदला और सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में चला गया। पायलट से संपर्क नहीं होने पर इस्त्राइली अधिकारियों को हाईजैक की आशंका हुई और वायुसेना के लड़ाकू विमान रवाना किए गए। बाद में पता चला कि आपातकालीन स्थिति का कारण पायलटों के बीच हुई झड़प थी।

फॉर्म-6 से 2003 वाला सवाल हटाया

एसआईआर में नाम कटे तो दोबारा जुड़वाना आसान

एजेन्सी, नई दिल्ली



चुनाव आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म-6 में बड़ा बदलाव किया है। अब SIR में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका, माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म-6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटा दिया गया है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नाम बिना जांच के जुड़ जाएगा। वोटर बनने की पात्रता की जांच पहले की तरह होगी। फॉर्म-6 की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहेगी। यह बदलाव फिलहाल सिर्फ उन राज्यों में लागू है, जहां रक्फ़पूरा हो चुका है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस पर आपत्ति जताई थी। फॉर्म 6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए होता है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म 6 में रक्फ़से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी।

उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। विवेक जोशी ने कहा कि फॉर्म 6 नियमों के तहत तय फॉर्म है, इसलिए इसमें बदलाव के लिए पहले नियमों में संशोधन जरूरी है। वहीं, सुखबीर सिंह संधू ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़े गए हिस्से को अनधिकृत और अवैध बताते हुए उसे हटाने की बात कही थी।

10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हुआ एसआईआर

एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। एसआईआर के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में ळश्ड ने जीत हासिल की है।

मेडल टैली में सातवें नंबर पर पहुंचा भारत, ईरान को पीछे छोड़ा

एशियाड में भारत को 10वां गोल्ड : तीरंदाजी में 3, शूटिंग में 1 गोल्ड

एजेन्सी, नई दिल्ली





भारत ने एशियन गेम्स के 11वें दिन 4 गोल्ड जीते। इनमें 3 गोल्ड तीरंदाजी और 1 शूटिंग में आया। इसके साथ भारत के 10 गोल्ड समेत 60 मेडल हो गए हैं। वह ईरान को पीछे छोड़कर मेडल टैली में 7वें नंबर पर पहुंच गया है।

बुधवार को पहला गोल्ड विमेंस कंपाउंड आर्चरी टीम ने जीता। इसके बाद चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी में गोल्ड जीता। नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी को शूटिंग में गोल्ड मिला। दिन का चौथा गोल्ड कंपाउंड आर्चरी के पुरुष टीम इवेंट में साहिल, गणेश और कुशल ने जीता।

आर्चरी में दिन के तीनों गोल्ड भारत के नाम

भारत ने कंपाउंड आर्चरी के तीनों इवेंट में गोल्ड जीते। विमेंस टीम ने चीन को 238-234 से हराकर अपने खिताब का बचाव किया। मिक्स्ड टीम फाइनल में चिकिता और साहिल का मुकाबला साउथ कोरिया की पार्क जंगयून और चोई योंगही से था। भारत ने शूट-ऑफ में गोल्ड अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट के लिए कोटा भी हासिल किया। पुरुष टीम फाइनल में साहिल, गणेश और कुशल की टीम ने चीन को 238-237 से हराया। भारत शुरूआती एंड में 58-60 से पीछे था, लेकिन इसके बाद भारतीय तीरंदाजों ने लगातार शानदार निशाने लगाए। फाइनल के बाद के 180 में भारत ने 180 अंक हासिल किए। साहिल ने अपने सभी 8 शॉट में 10 अंक बनाए, जबकि गणेश और कुशल ने भी दबाव के बीच लगातार 10 लगाए।

नीरू-किनान ने शूटिंग में दिलाया गोल्ड

ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल में नीरू ढांडा और किनान चेनाई ने भारत को गोल्ड दिलाया। भारत ने शुरूआत में 10 में से 6 हिट किए थे और एक समय चार टीमों में सबसे नीचे था। इसके बाद दोनों ने एक भी टारगेट मिस नहीं किया और शानदार वापसी करते हुए गोल्ड जीता। भारत ने कतर को सिर्फ एक अंक से पीछे छोड़ा। चीन ने ब्रॉन्ज जीता। नीरू का यह इन गेम्स में दूसरा गोल्ड है। इससे एक दिन पहले उन्होंने विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता था।

हॉकी: साउथ कोरिया को 2-0 हराकर फाइनल में भारत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए इशिका ने पेनल्टी कॉर्नर की वैरिएशन पर गोल किया, जबकि कप्तान सलिमा ने दूसरे हाफ में बढ़त दोगुनी की। अब भारत का गोल्ड मेडल मैच चीन से होगा। यह मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाएगा।

बॉक्सिंग में 2 ब्रॉन्ज, लवलीना फाइनल में

बॉक्सिंग में प्रियंका घंघास को विमेंस 60 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की यांग चेंग्यू से 4-1 से हार मिली। उन्हें ब्रॉन्ज मिला। कपिल पोखरियाने पुरुषों के 90 किग्रा सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के तुराबेक खाबिबुल्लाएव के खिलाफ 4-1 से हार के बाद ब्रॉन्ज जीता।

रेसलिंग: सुनील कुमार को ब्रॉन्ज

सुनील कुमार ने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किग्रा में ब्रॉन्ज जीता। सेमीफाइनल में जापान के ताइजो योशिदा से 11-0 की हार के बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम रॉबर्ट्स को 9-0 से हराया। यह हांगझोउ के बाद सुनील का लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज है। वह एशियन गेम्स में ग्रीको-रोमन रेसलिंग के दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने।

न्यूज ब्रीफ

नर्मदापुरम यार्ड के समपार फाटक क्रमांक 233 04 अक्टूबर तक रहेगा सड़क यातायात बंद

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल द्वारा रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नर्मदापुरम यार्ड स्थित ईदगाह समपार फाटक क्रमांक 233 (किमी 763/26ठ-30ठ) पर आवश्यक अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। समपार फाटक की संरक्षा एवं कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए यहां ओवरहॉलिंग कार्य किया जाएगा। निर्धारित अनुरक्षण कार्य के दौरान समपार फाटक क्रमांक 233 को 29 सितम्बर 2026 को प्रातः 08:00 बजे से 04 अक्टूबर 2026 को सायं 18:00 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा। इस दौरान फाटक से किसी भी प्रकार के सड़क यातायात का आवागमन नहीं हो सकेगा। रेल प्रशासन द्वारा यह कार्य समपार फाटक पर आवश्यक अनुरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेल एवं सड़क दोनों यातायात की संरक्षा बनाए रखने तथा भविष्य में सुरक्षित एवं सुचारु परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने नर्मदापुरम क्षेत्र के आम नागरिकों, वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकताओं से अपील की है कि निर्धारित अवधि में समपार फाटक क्रमांक 233 का उपयोग करने से बचें तथा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही, कार्य के दौरान लगाए गए यातायात संबंधी निदेर्शों एवं संकेतकों का पालन करते हुए रेल प्रशासन के साथ सहयोग करें। रेल प्रशासन को हुई असुविधा के लिए खेद है तथा आमजन से रेल संरक्षा के हित में सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1 अक्टूबर को होगा सामूहिक श्रमदान

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 के अंतर्गत 1 अक्टूबर को एक दिन, एक घंटा, एक साथ अभियान के तहत कंपनी मुख्यालय सहित क्षेत्रीय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सामूहिक श्रमदान एवं स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान का उद्देश्य कार्यालय परिसरों में स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सामूहिक सहभागिता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थल, कक्ष, टेबल, अलमारी, फाइल एवं अभिलेखों को व्यवस्थित करने के साथ ही आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई में सहभागिता करेंगे। मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्री राकेश शर्मा ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कंपनी मुख्यालय, गोविंदपुरा, भोपाल स्थित प्रबंध संचालक कार्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर स्वच्छता कर्मियों के योगदान के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें दस्ताने एवं एप्रन प्रदान किए जाएंगे तथा सम्मानित किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रीय संगोष्ठी नाड़ी विश्लेषण-2026 का आयोजन 6 अक्टूबर को

भोपाल। पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन (म.प्र.) के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी नाड़ी विश्लेषण-2026 का आयोजन 6 अक्टूबर 2026 को रजत जयंती ऑडिटोरियम में किया जाएगा। संगोष्ठी का उद्देश्य नाड़ी परीक्षा के शास्त्रीय सिद्धांतों, चिकित्सकीय उपयोगिता एवं वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता के साथ-साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में इसके वैज्ञानिक एवं अनुसंधानात्मक पक्ष पर विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श करना है। संगोष्ठी में देशभर से प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य तपन कुमार, वैद्य संजय पी. छाजेड, वैद्य सुशांत मिश्रा, डॉ. भाग्यश्री गावंडे, डॉ. नवीन चंद्र जोशी, डॉ. प्रज्ञान त्रिपाठी एवं डॉ. गायत्री आर. मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे।

ओडिशा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दल ने किया भोपाल की आधुनिक अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं का अवलोकन

सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत 28 सदस्यीय दल ने राजा भोज सेतु, सांदीपनि विद्यालय, आयुर्वेद संस्थान और वन विहार का किया भ्रमण





एक सत बुलेटिन, भोपाल

सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित अंतरराज्यीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्सचेंज कार्यक्रम में ओडिशा से आए 28 सदस्यीय दल ने राजधानी भोपाल की आधुनिक अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं का अवलोकन किया। दल को परिवहन अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं और किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यप्रदेश के विकास कार्यों, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक धरोहर से अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों को परिचित कराना है।

भ्रमण के दौरान दल ने राजा भोज सेतु का अवलोकन कर इसकी केबल-स्टेड तकनीक और संरचना की विशेषताओं को जाना। इसके बाद सदस्यों ने राजा भोज मार्ग से गुजरते हुए भोजताल के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन किया। इस दौरान दल को राजधानी की आधुनिक अधोसंरचना के साथ झीलों और प्राकृतिक परिवेश को देखने का अवसर मिला। दल ने टी.टी. नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय का भ्रमण कर आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। अपनी अधोसंरचना एवं विविध सह-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत इस विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती संगीता सक्सेना ने सदस्यों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों और सांदीपनि विद्यालयों की विशेषताओं से अवगत कराया।

इसके पश्चात दल ने पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वायत्त आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का भ्रमण किया। प्राचार्य श्री उमेश शुक्ला ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संस्थान की शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय गतिविधियों की जानकारी दी। दल ने पंचकर्म केंद्र का अवलोकन कर पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार, कायाकल्प चिकित्सा और संस्थान में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जाना।

बुधवार सुबह दल ने भोजताल के किनारे स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। सदस्यों ने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीवों का अवलोकन किया और राजधानी की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर को देखा। ओडिशा से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भोपाल की आधुनिक अधोसंरचना, शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय सुविधाओं, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। सदस्यों ने भ्रमण को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें मध्यप्रदेश के विकास कार्यों और राजधानी की विशिष्टताओं को समझने का अवसर मिला।

नर्सिंग विद्यार्थियों ने उप मुख्यमंत्री शुक्ल का जताया आभार

सरकार विद्यार्थियों के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल



एक सत बुलेटिन, भोपाल

नर्सिंग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। परिणाम जारी होने से विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई, उच्च कक्षाओं में प्रवेश एवं करियर से जुड़ी बाधाओं का समाधान हुआ है। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर नर्सिंग विद्यार्थियों एवं विभिन्न प्रतिनिधियों ने आज भोपाल स्थित उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के निवास कार्यालय में भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्यायालय के समक्ष छात्र हित का पक्ष मजबूती से रखा। न्यायालय के आदेश के परिपालन में परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। सरकार विद्यार्थियों के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

विद्यार्थियों एवं प्रतिनिधियों ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होने से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी आगे की शिक्षा एवं करियर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विद्यार्थियों एवं प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया तथा छात्र हित में किए गए प्रयासों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत मैत्री योजना से सचिन तिवारी बने आत्मनिर्भर

8 हजार मासिक आय, मैत्री योजना से बढ़कर हुई लगभग 30 हजार

एक सत बुलेटिन, भोपाल

ग्राम बावली, ग्राम पंचायत पादां, विकासखंड सारंगपुर, जिला राजगढ़ निवासी श्री सचिन तिवारी ने कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद खेती को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया। अतिरिक्त आय के लिए वे समय मिलने पर एक दुकान पर भी कार्य करते थे। सीमित रोजगार अवसरों के कारण उनकी मासिक आय लगभग 8,000 थी।

इसी दौरान विकासखंड अधिकारी डॉ.अमित शाक्या ने उन्हें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत संचालित मैत्री योजना की जानकारी दी। उन्होंने योजना के उद्देश्य, प्रशिक्षण और मैत्री कार्यकर्ता के रूप में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों के बारे में सचिन तिवारी को जानकारी दी। मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से प्रेरित होकर श्री तिवारी ने योजना से जुड़ने का निर्णय लिया।

योजना के अंतर्गत उन्होंने तीन माह का प्रशिक्षण भोपाल में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में मैत्री कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं प्रारंभ कीं। अब वे गांव-गांव जाकर पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन से संबंधित आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।



आय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि

मैत्री योजना से जुड़ने से पहले श्री सचिन तिवारी खेती, दूध विक्रय और अन्य छोटे-मोटे कार्यों से लगभग 8,000 प्रतिमाह आय अर्जित करते थे। मैत्री कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं प्रारंभ करने के बाद उनकी वर्तमान मासिक आय बढ़कर लगभग 30,000 हो गई है। इस प्रकार उनकी आय में करीब 22,000 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई आय से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें स्थायी स्वरोजगार के साथ भविष्य के प्रति आत्मविश्वास भी मिला है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

श्री सचिन तिवारी बताते हैं कि मैत्री योजना उनके लिए केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का अवसर साबित हुई है। योजना के माध्यम से मिले प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से उन्हें पशुपालकों की सेवा करने के साथ अपनी आजीविका को मजबूत करने का अवसर मिला।

वे योजना की जानकारी देने और प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए विकासखंड अधिकारी डॉ. अमित शाक्या के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। श्री तिवारी का कहना है कि वे भविष्य में भी पूरी निष्ठा और लगन से पशुपालकों को सेवाएं प्रदान करते हुए पशु स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास में योगदान देते रहेंगे।

सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर मिले तो ग्रामीण युवा अपने हुनर को स्वरोजगार में बदलकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। श्री सचिन तिवारी की सफलता की कहानी इसी विश्वास को साकार करती है।

शिकायत से समाधान तक: एक माह में तैयार हुआ पुस्तकालय

जन विश्वास अभियान के तहत मंगालिया हाट में बालिका की मांग बनी बच्चों के लिए नई सुविधा

एक सत बुलेटिन, भोपाल

जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम पंचायत मंगालिया हाट, जनपद पंचायत फंदा में एक बालिका की मांग को महज शिकायत के रूप में दर्ज करने के बजाय समयबद्ध कार्रवाई करते हुए एक माह के भीतर पुस्तकालय का निर्माण कर दिया गया। ग्राम की बालिका कु. खुशबू ने गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत ने इस मांग को प्राथमिकता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही शुरू की और एक माह में पुस्तकालय तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कराईं।



बच्चों को मिला अध्ययन और पठन-पाठन का बेहतर अवसर

पुस्तकालय के निर्माण से ग्राम के बच्चों को अब स्थानीय स्तर पर अध्ययन और पठन-पाठन के लिए एक सुलभ एवं सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किताबों और अध्ययन सामग्री के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

जनभागीदारी से पुस्तकालय को मिला नया आयाम

पुस्तकालय को उपयोगी और समृद्ध बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशंस द्वारा पुस्तकों का सहयोग/दान भी किया गया। पुस्तकों की उपलब्धता से बच्चों के लिए पठन-पाठन की सामग्री सुनिश्चित हुई और पुस्तकालय को अधिक उपयोगी बनाने में जनभागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जिस बच्ची ने मांग रखी, उसी के हाथों हुआ लोकार्पण

इस पहल की खास बात यह रही कि जिस बालिका खुशबू ने गांव में पुस्तकालय की मांग रखी थी, उसी के हाथों नव निर्मित पुस्तकालय का लोकार्पण कराया गया। इससे बच्चों में अपने गांव के विकास कार्यों के प्रति स्वामित्व, सहभागिता और विश्वास की भावना को बढ़ावा देने का संदेश मिला।

शिकायत बनी समाधान की मिसाल

जन विश्वास अभियान के तहत सामने आई इस पहल ने यह दशार्या कि नागरिकों की मांगों को प्राथमिकता और समयबद्धता के साथ लिया जाए तो शिकायतें ठोस समाधान में बदली जा सकती हैं। एक माह के भीतर पुस्तकालय का निर्माण, पुस्तकों का सहयोग और मांग रखने वाली बालिका के हाथों लोकार्पण–पूरी प्रक्रिया ने जनभागीदारी और प्रशासनिक तत्परता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

जन विश्वास अभियान का संदेश स्पष्ट है– शिकायत केवल सुनी नहीं गई, बल्कि एक माह में समाधान बनकर सामने आई और उस समाधान का उद्घाटन उसी बच्ची ने किया, जिसने इसकी मांग रखी थी।

डीआरएम ने 1 अधिकारी सहित 24 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को दी विदाई



एक सत बुलेटिन, भोपाल

पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल में रेल सेवा के प्रति वर्षों तक समर्पित भाव से योगदान देने वाले सितम्बर 2026 में सेवानिवृत्त हुए 01 अधिकारी एवं 23 कर्मचारियों सहित कुल 24 रेलकर्मियों को मंडल कार्यालय में आयोजित गरिमामय समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। समारोह की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी ने की।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के दीर्घकालीन सेवाकाल एवं रेल संगठन में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया तथा उनके सुखद, स्वस्थ एवं समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

सितम्बर माह में सेवानिवृत्त हुए 24 रेलकर्मियों में 01 राजपत्रित अधिकारी सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता श्री अरुण जोशी तथा 23 कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने मुख्य टिकट परीक्षक, लोको पायलट, तकनीशियन, हेल्पर, मुख्य कार्यालय अधीक्षक सहित विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हुए सभी 24 रेलकर्मियों को अंतिम निपटान राशि के रूप में कुल ?11.58 करोड़ का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को आई-पास पोर्टल के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश, मानार्थ पास, परिचय पत्र तथा उदारीकृत चिकित्सा सुविधा कार्ड भी प्रदान किए गए।

जबलपुर मेडिकल कॉलेज और एनसीएल के बीच एमओयू:

अब मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव होगी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

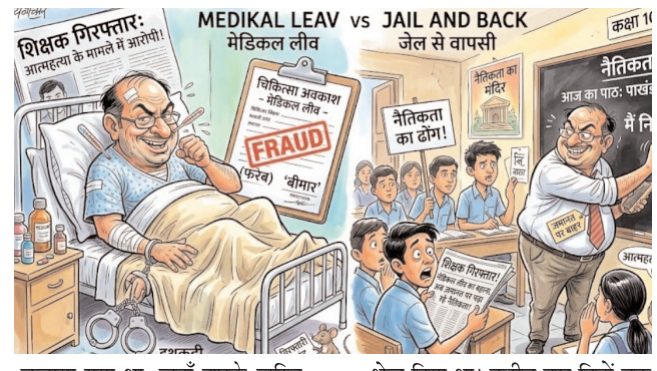


मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) साइन किया गया है। इस एमओयू के तहत एनसीएल ने अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व) फंड से मेडिकल कॉलेज को करीब 3 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक चिकित्सा मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इस सहयोग की सबसे बड़ी खासियत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग वैन है, जिसके माध्यम से अब ग्रामीण अंचलों में घर-घर और गाँव-गाँव जाकर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, एनसीएल सिंगरौली द्वारा प्रदान किए गए 3 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड से हाई-एंड डिजिटल मैमोग्राफी मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड यूनिट और एक पूरी तरह सुसज्जित आधुनिक मोबाइल वैन तैयार की गई है। इस विशेष वैन के भीतर मैमोग्राफी टेस्ट के अलावा सैंपल कलेक्शन और मरीजों की काउंसलिंग करने की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। यह मोबाइल वैन सप्ताह में 5 दिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा करेगी। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता (डीन) डॉ. नवनीत सक्सेना ने बताया कि इस आधुनिक पहल से महाकौशल अंचल में महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के मामलों की शुरुआती स्टेज में ही पहचान करने और समय पर इलाज शुरू करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। गाँव-गाँव शिविर लगाकर होगी 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता की कमी के कारण अक्सर गंभीर बीमारियां छिपी रह जाती हैं, लेकिन अब यह मोबाइल वैन इस दूरी और परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगी। इस वैन में विशेष रूप से महिला टेक्नीशियन और प्रशिक्षित नर्स तैनात रहेंगी, जो गाँव-गाँव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की पूरी तरह निशुल्क जाँच करेंगी। यदि जाँच के दौरान किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर या अन्य संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाएगा, जहाँ उनका संपूर्ण उपचार आयुष्मान योजना के तहत पूरी तरह निशुल्क किया जाएगा। एनसीएल के अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए यह उनका एक बहुत बड़ा कदम है, और वे सीएसआर फंड के माध्यम से केवल सिंगरौली ही नहीं बल्कि पूरे जबलपुर संभाग के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नाबालिग छात्रा की आत्महत्या मामले में आरोपी शिक्षक की लापरवाही

अपनी गिरफ्तारी छुपाकर मेडिकल लीव पर रहा और जमानत मिलते ही फिर शुरू किया पढ़ाना

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक नाबालिग किशोरी की आत्महत्या के मामले में आरोपी सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी गिरफ्तारी और जेल जाने की बात शिक्षा विभाग से पूरी तरह छुपा कर रखी। आरोपी शिक्षक ने पुलिस हिरासत और करीब 10 दिन जेल में बिताने के उस दौर को छुपाने के लिए मेडिकल लीव का सहारा लिया और जमानत पर बाहर आते ही दोबारा स्कूल पहुँचकर बच्चों को पढ़ाने लगा। इस गंभीर लापरवाही और मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या था पूरा मामला और आरोप?

यह पूरा मामला एक नाबालिग किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आत्महत्या से जुड़ा है। आरोप है कि घटना से पहले मृतका किशोरी को पंचायत में बुलाया गया था, जहाँ उसके चरित्र और गतिविधियों को लेकर कई प्रकार की आपत्तिजनक बातें कहीं गई। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि उसे सरेआम 'चोर' और 'डायन' जैसे गंभीर ताने और आरोप तक झड़ने पड़े थे। इस सामाजिक प्रताड़ना और मानसिक तनाव से आहत होकर किशोरी ने जहर खा लिया था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। गिरफ्तारी छुपाई और मेडिकल लीव से दर्ज कराई गैरहाजिरी इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सरकारी शिक्षक संतोष कुमार पटेल को गत 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। करीब दस दिनों तक जेल में रहने के बाद जब उसे जमानत मिली, तो वह चुपचाप बाहर आया और सगड़ा-छपनी स्थित स्कूल में दोबारा पढ़ाने के लिए पहुँच गया। हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षक ने अपनी गिरफ्तारी या जेल जाने की भनक तक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं लगने दी। स्कूल रिकॉर्ड में अपनी इस अनुपस्थिति को छुपाने के लिए उसने शातिर तरीके से मेडिकल लीव (चिकित्सा अवकाश) का आवेदन लगवाकर अपनी गैरहाजिरी को ढक लिया, जो अब विभागीय जांच और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

उखरी चौक पर हादसा: स्कूल बस की चपेट में आने से महिला की मौत

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के व्यस्ततम उखरी चौक पर मंगलवार दोपहर एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहाँ एक तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आने से करीब 30 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भयानक हादसे के बाद मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोहलपुर निवासी मृतका अलका पांडे मंगलवार दोपहर को उखरी चौक के पास से गुजर रही थीं। इसी दौरान 'लिटिल वर्ल्ड स्कूल' की एक बस वहाँ पहुँची और अनियंत्रित होकर महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस महिला को कुचलते हुए उसके ऊपर से निकल गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर शहर के भीतर बेकाबू स्कूल बसों के संचालन, उनके चालकों की लापरवाही, प्रशासनिक निगरानी और आम राहगीरों की सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और उस वक्त बस की गति कितनी तेज थी, इन सभी बातों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसे के असल कारणों का पता लगाने में जुटी है।

जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 6 माह की मासूम आयुषी की मौत : उपचार व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल–नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में एक बार फिर उपचार व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ इलाज के दौरान छह महीने की मासूम बच्ची आयुषी की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में भारी लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने और बढ़ते हंगामे के बाद आखिरकार मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। मासूम बच्ची की अचानक हुई मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अस्पताल के आईसीयू या शिशु वार्ड में इलाज के दौरान ऐसी क्या गंभीर चूक हुई, जिसके कारण एक छह महीने की बच्ची की जान चली गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्ची को समय पर और सही डॉक्टर द्वारा जरूरी उपचार उपलब्ध कराया गया था या नहीं? इन सभी संवेदनशील सवालों के जवाब और सच का पता लगाने की जिम्मेदारी अब गठित की गई जांच कमेटी को सौंपी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इस कमेटी में अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों और वरिष्ठ डॉक्टरों को शामिल किया गया है, जो पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल करेंगे: डॉक्टर अरविंद शर्मा (अस्पताल अधीक्षक) डॉक्टर पवन घनघोरिया (शिशु रोग विभागाध्यक्ष) डॉक्टर रानू तिवारी मिश्रा (सदस्य) यह जांच कमेटी बच्ची के मेडिकल रिकॉर्ड, इलाज के दौरान बरती गई प्रक्रियाओं और परिजनों के बयानों के आधार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

जबलपुर में इस बार 35 फीसदी कम बारिश से चिंता में डूबा शहर

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के प्रमुख शहर जबलपुर में इस बार मानसून का सीजन अपने साथ राहत की जगह भविष्य की बड़ी चिंताएं छोड़ गया है। मानसून के विलंब से आने और जाते-जाते बेरुखी दिखाने के कारण इस साल शहर और जिले में पानी का बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस मानसून सीजन में जबलपुर में सामान्य औसत के मुकाबले करीब 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे आने वाले गर्मियों के दिनों में विकराल जलसंकट गहराने की पूरी संभावना बन गई है। 1300 मिमी के सामान्य कोटे के मुकाबले महज 845 मिमी बरसे बदरा मौसम विभाग और जलसंसाधन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 जून से लेकर 29 सितंबर तक के इस पूरे मानसून सीजन में जिलेभर में केवल 845.2 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है, जबकि जबलपुर का सामान्य औसत लगभग 1300 मिमी माना जाता है। इस प्रकार इस बार आसमान से उम्मीद के मुकाबले करीब 455 मिमी पानी कम बरसा है, जिससे जल स्रोतों का रीचार्ज होना तो दूर, तालाबों और जलाशयों का जलस्तर भी खतरे के निशान से काफी नीचे बना हुआ है। पिछले एक दशक में दूसरी सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड पिछले दस सालों के मौसमीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह दूसरा मौका है जब जबलपुर औसत वर्षा के आंकड़े से इतनी ज्यादा दूरी पर रह गया है। इससे पहले साल 2021 में सबसे कम महज 625.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अगली गर्मियों के मौसम में शहर के जलस्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया था और जनता को भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ा था। इस बार भी वैसी ही परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, जिससे प्रशासन और आम जनता दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर सीबीआई का शिकंजा

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) की भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेजों और जाली अंकसूचियों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 8 कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। विभाग द्वारा कराई गई आंतरिक दस्तावेजों की जांच में इन सभी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद इनकी सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी गई थीं। सीबीआई की विशेष टीम ने इनमें से 5 आरोपियों को जबलपुर और 3 को कटनी से दबोचा है। जांच का दायरा बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में ऐसे अन्य संदिग्ध कर्मचारियों की संख्या में भी भारी इजाफा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, डाक विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा के शैक्षिक प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों का उनके संबंधित बोर्डों के माध्यम से सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराया गया था। इस क्रॉस-चेकिंग के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कई अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई अंकसूचियां संबंधित शैक्षणिक बोर्डों द्वारा कभी जारी ही नहीं की गई थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि इन अभ्यर्थियों ने नौकरी हथियाने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों के शिक्षा बोर्डों के नाम से तैयार फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट के अनुसार, उपयोग किए गए ये जाली दस्तावेज मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और जम्मू-कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों के बोर्डों से संबंधित पाए गए।

30 साल पुराने रिश्वत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

निचली अदालत का आदेश बरकरार, तत्कालीन पटवारी को राहत

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने लगभग तीन दशक (30 साल) तक चले एक पुराने कानूनी विवाद में तत्कालीन पटवारी को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय एस. कलगांवकर की एकल पीठ ने तीन सौ रुपये की रिश्वत लेने से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी पटवारी को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को पूरी तरह उचित ठहराया है। इसके साथ ही, इस मामले में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। क्या था पूरा मामला? प्रकरण के अनुसार, सागर जिले के खुरई क्षेत्र में पदस्थ तत्कालीन पटवारी मुन्नालाल पर आरोप था कि उन्होंने 17 अक्टूबर 1996 को डुप्लीकेट भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता वीर सिंह से 300 रुपये की रिश्वत ली थी, जिसके बाद उन्हें रंगे हाथों पकड़े जाने का दावा किया गया था। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने दिसंबर 1997 में आरोपी पटवारी को आरोपों से दोषमुक्त (बरी) कर दिया था। जिला अदालत के इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने वर्ष 1998 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ की मुख्य टिप्पणियां और आधार: सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं और साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया: रिश्वत की मांग साबित नहीं: अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह विश्वसनीय रूप से साबित करने में असफल रहा कि रकम अवैध रूप से मांगी और स्वीकार की गई थी। रिश्वत की मांग की मूल रिकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट में सत्यापित नहीं की गई थी, न ही आरोपी की आवाज की पहचान कराई गई और न ही रिकॉर्डिंग की शुद्धता के पर्याप्त प्रमाण दिए गए, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। सरकारी बकाया से जुड़ा हो सकता है लेन-देन: राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने पर सामने आया कि शिकायतकर्ता वीर सिंह पर 325 रुपये और उस पर ब्याज की सरकारी बकाया राशि थी। गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर यह संभावना भी सामने आई कि बरामद किए गए 300 रुपये असल में सरकारी बकाया राशि की अदायगी से संबंधित हो सकते हैं।

डीजीटी और ईएसबी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती में सीआईटीएस की अनिवार्यता न होने पर हाईकोर्ट सख्त

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीएस) को अनिवार्य योग्यता न बनाए जाने का मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की संयुक्त पीठ ने प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को नोटिस जारी कर कड़ा जवाब तलब किया है। न्यायालय ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर प्रशिक्षण अधिकारी जैसे तकनीकी पद के लिए सीआईटीएस को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में इसे अनिवार्य किया जा चुका है। क्या है पूरा मामला और याचिका का आधार? यह याचिका छतरपुर निवासी सिपाही लाल अहिरवार एवं अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसकी पैरवी अधिवक्ता राहुल सिंह ठाकुर, श्रेयश राज त्रिपाठी और माहित प्यासी द्वारा की गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्त पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार ने आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए सीआईटीएस को अनिवार्य करने के संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश व पत्र भेजे थे। याचिका में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड जैसे पड़ोसी व अन्य राज्यों में सीआईटीएस की ट्रेनिंग को प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में इस अहर्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को अवगत कराया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और डीजीटी की आधिकारिक गाइडलाइंस के अनुसार, सीआईटीएस वह पाठ्यक्रम है जिसमें प्रशिक्षकों को केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि युवाओं को पढ़ाने और प्रशिक्षित करने की आधुनिक विधियों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीवीटी द्वारा आईटीआई के सभी प्रशिक्षकों के लिए सीआईटीएस को अनिवार्य घोषित किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इसके बिना ही प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया संचालित किए जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिस पर अब उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगा है।

संपादकीय

फॉर्म 6 का फ्रॉड

चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता, विपक्षी आंदोलन और राजनीति के निशाने पर हैं। कांग्रेस कार्यसमिति और शेष विपक्ष की सामूहिक मांग है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को निलंबित किया जाए। यदि संभव है, तो उसे रद्द ही कर दिया जाए। अभी तक जिन 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। यह कैसे संभव है, क्योंकि उनमें से 2.80 करोड़ से ज्यादा मतदाता तो दिवंगत (मृत) हो चुके हैं। शेष 10.57 करोड़ काटे गए नामों पर चुनाव आयोग को बाध्य किया जाना चाहिए। दिल्ली में यह मामला सामने आया है। बेला एस्टेट में अधिकतर झुग्गी-झोंपड़ियां थीं। लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए हुए थे और वे वहां बसे हुए थे। 2022-23 में उन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। वहां 728 वैध मतदाता रहते थे, जिनके पास चुनाव आयोग की मान्यता थी और वे लगातार मतदान करते रहे थे। झुग्गियां टूटीं, तो वे बेघर हो गए। एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ को उस जगह कोई नहीं मिला। किसी एक ने मतदाता पहचान पत्र दिखाया।

नतीजतन 728 में से 727 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन बेघरों के पास गए और मोबाइल पर ईआरओ से पूछा कि इतने नाम किस आधार पर काट दिए गए? बहरहाल जब यह खबर टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में आ गई कि बेला एस्टेट के बेघर परिवार फ्लाईओवर के नीचे जीने को विवश हैं, तो चुनाव आयोग ने अपने बीएलओ भी वहां भेजे। कटे हुए नामों के उन लोगों को फॉर्म 6 भर कर नया मतदाता बनने की सलाह दी गई। खबर बताई जाती है कि 418 लोगों से फॉर्म 6 भरवा भी लिए गए हैं।

अब नई मतदाता-सूची में उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यह संवैधानिक फ्रॉड खेला है। फॉर्म 6 उन लोगों के लिए है, जो बिल्कुल पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं। वे पहले कभी भी मतदाता न रहे हों। ऐसा घोषणा-पत्र भी भर कर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। लेकिन ये तो पहले भी मतदाता रहे हैं और उन्होंने एसआईआर में अधिकृत फॉर्म भी भरा था। क्या यह संवैधानिक कवायद है? यदि 418 काटे गए नाम, अंततः, मतदाता बन जाते हैं, तो शेष लोग भी मतदाता बनाए जा सकते हैं।

तो फिर एसआईआर का औचित्य क्या रहा? क्या इस तरह चुनाव आयोग फ्रॉड नहीं कर रहा है और फॉर्म 6 के साथ झूठे घोषणा पत्र भी नहीं भरवा रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जानकारी में यह पूरा मामला है, लिहाजा उनका आंदोलन सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के इस्तीफे पर केंद्रित है। राहुल को यकीन है कि अंततः प्रधानमंत्री मोदी ही सीईसी का इस्तीफा करवाएंगे, क्योंकि ज्ञानेश तो उन्हीं की कठपुतली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने तो प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा मांग लिया है।

फॉर्म 6 के इस कथित फजीवाड़े में भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी फंसे हैं। वह जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वह पंजाब के मतदाता थे और आप के प्रत्याशी थे, लेकिन बाद में आप के 7 राज्यसभा सांसद पालाबदल कर भाजपा में शामिल हो गए, तो अब उन्हें दिल्ली का मतदाता बनाया गया है। इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्थानांतरित होता है, तो मतदाता भी बदला जा सकता है। अलबत्ता संवैधानिक हेराफेरी न की जाए। बताया जाता है कि राघव चड्ढा से फॉर्म 6 भरवाया गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आप ऐसा कह रही है और अदालत में इसे चुनौती देने की बात भी पार्टी ने की है। दरअसल एसआईआर का मुद्दा बेहद पेचीदा हो गया है।

दिल्ली में ही 9 लाख से अधिक बांग्लादेशी बस चुके हैं। वे अभी तक मतदाता भी बने रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर के दौरान क्या चिह्नित किया है? सर्वोच्च अदालत में यह मामला विचाराधीन है और एक मामले में तो एसआईआर को अवैध करार देने की भी मांग की गई है। जो भी हश्र होगा, देखा जाएगा, लेकिन इस मुद्दे ने हमारी राजनीति को बिल्कुल विभाजित और विषाक्त बना दिया है। विपक्ष को चुनाव आयोग की मनमानियां पसंद नहीं हैं और सारा देश इस मसले पर आंदोलित है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिए हटाना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास वांछित बहुमत नहीं है, फिर भी इसके जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह का माहौल तो बन ही रहा है।

शक्ति संतुलन, कूटनीति और जलवायु संकट

विकेश कुमार बडोला

> ब्रिक्स हो अथवा संयुक्त राष्ट्र, सभी मंचों पर अब देश को न तो इंडिया लिखा जाता है और न बोला जाता है। अब देश का संबोधन भारत के रूप में होता है। यह हिंदुस्थानियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। लाख शासकीय कमियों के उपरांत भी विगत 12 वर्षों के भारतीय केंद्रीय शासन की विदेश नीति सबसे अच्छी नीति के रूप में साकार हुई है और इसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

विश्व में अनेक स्तर पर हो रहे युद्धों, दो या अधिक देशों के पारस्परिक सशस्त्र संघर्षों तथा अन्य राजनीतिक प्रतिकूलताओं व नकारात्मक प्रतिस्पद्धाओं के बीच संपन्न संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा में अत्यधिक हलचल रही। सन् 2014 के बाद महासभा में ऐसी हलचल प्रत्येक वर्ष हो रही है और आगामी वर्ष में तीव्र से तीव्रतम हो रही है। जब तक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों- अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के देशज हित सधते रहे, तब तक महासभा का आयोजन शेष विश्व के लिए एक साधारण आयोजन हुआ करता था। किंतु जब से उक्त पांच देशों के मध्य स्वार्थ साधने एवं शीर्ष पर स्थापित होने की स्पर्धा बढ़ी तथा इनके प्रतिस्पर्द्धी बनकर दुनिया के कुछ अन्य देश भी खड़े हुए हैं, तब से महासभा की वार्षिक बैठक आरोप-प्रत्यारोप का मंच बन गई है। पांच देशों के प्रतिस्पर्द्धी बनकर खड़े होने वाले देशों में सम्मिलित हैं भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। विशेषकर भारत में 2014 के बाद जो शासन तंत्र स्थापित हुआ और जिस प्रकार स्वदेशी गौरव के प्रति एक तीव्र शासकीय एवं लोकतांत्रिक हलचल होनी आरंभ हुई, उस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के प्रभुत्व में दबदबा बनाए रखने वाले प्रमुख पांच देशों में से अमरीका, चीन एवं ब्रिटेन को कुछ अधिक बेचैनी हो गई है। भारत, रूस एवं चीन के नेतृत्व में ब्रिक्स सहित दक्षिण एशियाई एवं मध्य पूर्वी देशों के बीच अमरीकी-यूरोपीय शासकीय प्रभुत्व को खंडित करने के लिए वैचारिक एवं व्यावहारिक स्तर पर जो नवचेतना जागृत हुई है, उसने भी विश्व को पिछले एक-डेढ़ दशक में पहले तो शीतयुद्ध में धकेला और अब उस कारण धीरे-धीरे विभिन्न स्तरों पर देशों के मध्य सशस्त्र संघर्ष भी बढ़ रहा है।

जिस प्रकार विश्व समय-समय पर शीतयुद्ध से प्रभावित रहा है, उसी प्रकार भारत के केंद्रीय कल्याणकारी भूमिका में अवतरित होने के बाद संपूर्ण विश्व में शीत-समन्वय की धारणा जड़ें जमा रही है। अघोषित रूप से भारत की विदेश नीति सर्वमान्य हो रही है। विदेशों में भारत के मानवतावादी सिद्धांत की प्रशंसा हो रही है। किसी भी मंच पर भारत का मत स्वार्थ से विलग जगहित के लिए होता है। इस भाव को दुनिया के अधिसंख्य देश पहचान रहे हैं। भारत के शत्रु देश भी इस भावना से भलीभांति परिचित हैं। इसीलिए वे भारतीय पराभव के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त हैं। महासभा के मंच पर जहां अधिसंख्य देशों एवं उनके प्रमुखों तथा प्रमुखों की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों ने अपने-अपने हितों के रक्षार्थ भाषण किया तथा अपने शत्रु देश के प्रति आक्रोश से भरकर अपनी-अपनी आपत्तियां प्रकट कीं, वहीं भारतीय प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अत्यंत शांत होकर, संयम एवं विनीत भावना के साथ वैश्विक युद्धजन्य संघर्षों, प्राकृतिक चुनौतियों, असमान सुख-सुविधाओं के वितरण, आदि मानवीयता-केंद्रित विषयों पर संभाषण किया तथा पारस्परिक सेवा व सहयोग के विचार के साथ विकसित होने के विचार पर बल दिया। हालांकि उन्होंने भी भारत के पारंपरिक शत्रु देश पाकिस्तान पर मंच से दोषारोपण किया, किंतु ऐसा आरोप कल्पना आधारित नहीं है। यह अनेक स्तर पर प्रामाणिक है। यह अलग बात है कि न तो अमरीका और न ही संयुक्त राष्ट्र ने इस पर आज तक गंभीरतापूर्वक विचार किया है। संयुक्त राष्ट्र की अप्रासंगिकता एवं अनुपयोगिता को स्वीकार करके ही तो दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया में ब्रिक्स जैसा संगठन वर्ष-प्रतिवर्ष वृहद आकार ले रहा है। इस संगठन की व्यावहारिक व उपयोगी कार्यप्रणालियों के कारण शनैः.शनैः जी-7 एवं जी-20 जैसे समूहों की आवश्यकता व उपयोगिता पर संकट मंडरा रहा है।

जी-7 एवं जी-20 जैसे समूहों के बल पर ही संयुक्त राष्ट्र की भी प्रासंगिकता है। ऐसे में यदि ब्रिक्स का आकार प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहा और इसमें यूरोप, अफ्रीका एवं दुनिया के अन्य द्वीपों के देश सदस्यों के रूप में जुड़ते रहे तो वास्तव में अमरीका, ब्रिटेन व यूरोप का वैश्विक प्रभाव अत्यंत कम हो जाएगा। इन्हीं चिंताओं से घिरकर अमरीका, ब्रिटेन के नेतृत्व में विश्व को निरंतर विभिन्न स्तर पर सशस्त्र युद्धों, आतंकी घटनाओं एवं लोकतंत्र के विरोध में अराजक आंदोलनों में धकेला जा रहा है। इस संवेदनशील स्थिति में पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र देश है, जो सर्वहित की बात करता है, जो परस्पर सहायता एवं सहयोग के बल पर विकसित होने का विकल्प सम्मुख रखता है, जो कठोर सशस्त्र संघर्षों के बीच भी समझौता, शांति एवं मानवता के मार्ग को चुनने की सलाह देता है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी भारत ने एस. जयशंकर के माध्यम से ऐसा ही किया है। विदेश मंत्री की बातों के मर्म को समझा जाए तो स्पष्ट होता है कि यह भारतीय अध्यात्म, दर्शन, धर्म एवं सर्वहितैषी भाव के केंद्रीय विचार का ही संभाषणीय प्रतिपादन है। ऐसी भावना का प्रतिनिधि भारत ही हो सकता है।

ब्रिक्स हो अथवा संयुक्त राष्ट्र, सभी मंचों पर अब देश को न तो इंडिया लिखा जाता है और न बोला जाता है। अब देश का संबोधन भारत के रूप में होता है। यह हिंदुस्थानियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। लाख शासकीय कमियों के उपरांत भी विगत 12 वर्षों के भारतीय केंद्रीय शासन की विदेश नीति सबसे अच्छी नीति के रूप में साकार हुई है और इसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि भारत विभिन्न प्रकार के संघर्षों में उलझी हुई दुनिया और इसके देशों के लिए सकारात्मक संभाषण करते हुए हरेक मंच को सकारात्मकता प्रदान करता है, किंतु वास्तविकता पर ध्यान लगाएं तो वह यही है कि संघर्षों के लिए दोषी देश केवल मंच की परिधि में ही रहकर भारत या किसी अन्य देश की ऐसी सकारात्मकता पर ध्यान लगाते हैं, और मंचावधि समाप्त होते ही पुनः अपने-अपने हठ, स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति में लग जाते हैं। इस समय जगत में सशस्त्र संघर्ष ही एक प्रमुख एवं दीर्घ कारण नहीं, जो चिंता का विषय है, बल्कि जलवायु की प्रतिकूलता सबसे बड़ा चिंतनशील विषय है। दुर्भाग्य से यह विषय विकसित देशों के लिए चिंता एवं चिंतन का विषय है ही नहीं।

भारत के लिए बढ़ती टैरिफ चुनौतियां

डा. जयंतीलाल भंडारी

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाल ही के महीनों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए-नए आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणवादी कदमों से भारत के लिए आर्थिक-व्यापारिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमरीका के व्यापार, कृषि, बौद्धिक संपदा और श्रम बाजार से जुड़े नीतिगत बदलावों के कारण उत्पन्न हुई है



हाल ही में 18 सितंबर को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले भारत-चीन समेत पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाले बिल ह्यलिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026ह्ल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। यह कानून हस्ताक्षर किए जाने के 30 दिनों के भीतर प्रभावी होगा। यह कानून स्वचालित रूप से तुरंत टैरिफ लागू नहीं करता है। किस देश पर कितना टैरिफ लगाना है या राष्ट्रीय हित में किसे छूट देनी है, इसका अंतिम निर्णय अमरीकी राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए 24 सितंबर को अमरीका की यात्रा कर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नायाब तोहफा देते हुए कहा कि 10 जनवरी 2027 तक चीन पर 100 प्रतिशत या अन्य कोई नया टैरिफ लागू नहीं होगा। लेकिन भारत पर टैरिफ लागू होने की चुनौती बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि अमरीका के इस नए टैरिफ कानून का प्राथमिक उद्देश्य रूस और ईरान के ऊर्जा स्रोतों से होने वाली राजस्व आय पर रोक लगाना है। इस कानून से भारत सहित दुनिया के कई देश प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। रूस और ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में भारत और चीन सबसे प्रमुख हैं।

निसंदेह भारत के लिए यह स्थिति आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक तरफ जहां रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, वहीं दूसरी ओर अमरीका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यदि अमरीका भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करता है, तो इससे भारतीय निर्यात को भारी झटका लग सकता है। ऐसे में अमरीकी संसद द्वारा रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किए जाने और 100 प्रतिशत तक टैरिफ के प्रावधान पर भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि 140 करोड़ से अधिक देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा और हित सर्वोपरि हैं, जिनसे कोई समझौता नहीं होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और ऐसे में भारत किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना, बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेगा। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाल ही के महीनों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए-नए आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणवादी कदमों से भारत के लिए आर्थिक-व्यापारिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमरीका के व्यापार, कृषि, बौद्धिक संपदा और श्रम बाजार से जुड़े नीतिगत बदलावों के कारण उत्पन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक आदेश के माध्यम से ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के अतिरिक्त शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है और वीजा नियमों की जांच को पहले से अधिक सख्त कर दिया है। इस फैसले के तहत अमरीका के विदेश, श्रम और गृह सुरक्षा मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे वीजा आवेदनों को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि नियोक्ता ने हाल में अमरीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला न हो या भविष्य में छंटनी की योजना न बनाई हो। हालांकि, इस भारी भरकम शुल्क से उन विदेशी नागरिकों को राहत दी गई है जो पहले से अमरीका में छात्र वीजा एफ-1 पर रह रहे हैं या अपने मौजूदा वीजा का नवीनीकरण करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, श्रम मंत्री को 30 दिनों के भीतर श्रम स्थिति आवेदनों की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले का सबसे गहरा असर भारतीय पेशेवरों और आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि कुल मंजूर एच-1बी वीजा में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी करीब 71 प्रतिशत है। 2025 में इस शुल्क के लागू होने के बाद से ही बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के पंजीकरण में करीब 92 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। यह नीति न केवल तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र बल्कि ग्रामीण अमरीका में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले भारतीय डाक्टरों को भी प्रभावित करेगी।

इसी तरह गत 11 सितंबर को ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी और अन्य गैर-आप्रवासी वीजा धारकों की नौकरी छूटने के बाद मिलने वाली 60 दिन की मोहलत को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में लागू नियम के अनुसार, नौकरी जाने पर विदेशी कर्मचारियों को अमरीका में रहकर दूसरी नौकरी खोजने, वीजा स्थिति बदलने या देश छोड़ के लिए 60 दिन का समय मिलता है। यदि नया प्रस्ताव लागू होता है, तो नौकरी समाप्त होते ही कर्मचारी का वैध गैर-आप्रवासी दर्जा भी तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नई नौकरी मिलने पर भी कर्मचारी को अमरीका से बाहर जाकर दूतावास के जरिए पुनः आवेदन करना पड़ सकता है। इस कदम का सबसे बड़ा असर अमरीका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा, जो बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा पर निर्भर हैं। यह प्रस्ताव केवल एच-1बी तक सीमित नहीं है, बल्कि एल-1, ओ-1 और टीएन जैसी अन्य वीजा श्रेणियों पर भी लागू होगा। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग का तर्क है कि इससे कर्मचारी के रहने की वैधता और उसकी नौकरी के बीच सीधा संबंध बनेगा तथा प्रशासनिक बोझ कम होगा। फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। इस पर दो महीने तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। तब तक पुरानी 60 दिन की व्यवस्था लागू रहेगी। इसी प्रकार व्हाइट हाउस के ह्यऑफिस ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीह्ल की ह्यद ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैमह्ल रिपोर्ट में भारत समेत 40 से अधिक देशों पर चीन द्वारा अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए अवैध री-रूटिंग नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है।

भारत सरकार ने अमरीका की इस रिपोर्ट के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में सख्त कस्टम्स रूल्स और मजबूत कानून लागू हैं। इसके अतिरिक्त अमरीकी प्रशासन द्वारा आयातित जेनेरिक औषधियों पर चरणबद्ध तरीके से 1 अगस्त 2026 से नई शुल्क नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2028 तक (शुरूआती दो वर्षों के लिए) आयातित दवाओं को शुल्क से मुक्त रखा गया है, ताकि अमरीकी बाजार में दवा आपूर्ति बाधित न हो। इसके पश्चात, 1 अगस्त 2028 से 31 जुलाई 2029 तक दवाओं के मूल्य पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क लागू किया जाएगा। अंततः 1 अगस्त 2029 के बाद इस शुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह अमरीका की ओर से भारत के लिए बढ़ती आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत को अमरीका के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना होगा। एक संतुलित और औपचारिक व्यापार समझौता भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे औषधियां, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प पर अमरीकी शुल्क दरों को शून्य या न्यूनतम स्तर पर ला सकता है। लेकिन इस समय अमरीकी संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। अमरीका पर अत्यधिक निर्भरता घटाने के लिए लैटिन अमरीका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के गैर-पारंपरिक बाजारों में निर्यात का विस्तार करना आवश्यक है। साथ ही, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को शीघ्र लागू करते हुए व्यापारिक विविधता सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीद करें कि सरकार ट्रंप के टैरिफ और संरक्षणवादी चुनौतियों के बीच नई व्यापार साझेदारियों, निर्यात बाजारों के विविधीकरण और आर्थिक-वित्तीय नीतियों के जरिए देश के आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी।

न्यूज ब्रीफ

ग्वालियर में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान का अनूठा आयोजन

ग्वालियर। शहर के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सराहने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान की ओर से आगामी 1 अक्टूबर को एक बेहद प्रेरणादायक और गरिमामयी आयोजन होने जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग के इस विशेष सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु के 37 बुजुर्गों का मुख्य रूप से सम्मान किया जाएगा। यह पूरा भव्य आयोजन जैन छात्रावास, हॉस्पिटल रोड पर दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें शहर के कई गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संस्था के अध्यक्ष इंजी. एसके गुप्ता और सचिव एमके जैन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ाने के लिए कई प्रतिष्ठित हस्तियां बतौर अतिथि शामिल होंगी। इस समारोह में नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि एएसपी सुजावल जग्गा और एसडीएम डबरा नवकिरन कौर जग्गा विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रो. आरजे राव और जीडी लड्ढा मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखेंगे, तथा इस पूरे गरिमामयी समारोह की अध्यक्षता संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल द्वारा की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज को मार्गदर्शन देने वाले वरिष्ठ जनों के लंबे जीवन के अनुभवों का सम्मान करना और नई पीढ़ी को उनके प्रति आदर भाव सिखाना है।

2 अक्टूबर को होगा शैक्षिक परिसंवाद, डॉ. अतुल कोठारी होंगे मुख्य वक्ता

ग्वालियर। देश के उज्ज्वल भविष्य और शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के उद्देश्य से जीवाजी विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (नई दिल्ली, मध्यभारत प्रांत) के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष शैक्षिक परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगामी 2 अक्टूबर को सायं 4 बजे जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित गालव सभागार में आयोजित होगा, जिसका मुख्य केंद्रीय विषय 'विकसित भारत 2047 हेतु शिक्षा' रखा गया है। इस गरिमामयी शैक्षिक परिसंवाद में शिक्षा जगत के कई दिग्गज और प्रतिष्ठित प्रशासनिक चेहरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी उपस्थित रहेंगे, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में शिक्षा की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया होंगे, जबकि इस संपूर्ण संगोष्ठी की अध्यक्षता जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत द्वारा की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहाँ वे राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के भविष्य को लेकर मंथन कर सकें।

कंटेनर का किराया 150% बढ़ने से स्टोन एक्सपोर्ट संकट में

ग्वालियर। ग्वालियर के विश्वप्रसिद्ध बलुआ पत्थर (स्टोन) का कारोबार इन दिनों एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश से लेकर यूरोप तक अपनी खास पहचान रखने वाले इस स्टोन उद्योग को शिपिंग लागत में अचानक हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने तगड़ा झटका दिया है। यूरोप के करीब 27 देशों में होने वाले स्टोन उत्पादों के निर्यात का पूरा गणित कंटेनर किराए में हुई भारी वृद्धि के कारण बिगड़ गया है, जिससे स्थानीय कारोबारियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। व्यापारियों के मुताबिक, यूरोप जाने वाले शिपिंग कंटेनर का किराया सीधे तौर पर करीब 150 प्रतिशत तक बढ़ गया है। जो कंटेनर पहले आसानी से लगभग 2 हजार अमेरिकी डॉलर में बुक हो जाता था, उसके लिए अब कारोबारियों को 5 हजार डॉलर से भी ज्यादा की रकम चुकानी पड़ रही है। स्थिति यह है कि कुछ मामलों में तो यह किराया बढ़कर 5,400 डॉलर तक जा पहुंचा है। इस भारी-भरकम बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह खाड़ी देशों में चल रहा तनाव और युद्ध है, जिसके चलते कार्गो जहाजों को लंबे और महंगे रूट से घूमकर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा, वापसी के फेरे में जहाजों को पर्याप्त माल न मिल पाने के कारण भी शिपिंग कंपनियों ने किराए में यह रिकॉर्ड इजाफा किया है। विदेशी बाजार में महंगे हुए ग्वालियर के स्टोन उत्पाद शिपिंग लागत में इस अप्रत्याशित उछाल का सीधा असर ग्वालियर के स्टोन उत्पादों की कीमतों पर पड़ा है, जो अब यूरोपियन बाजारों में काफी महंगे साबित होने लगे हैं।

चेतकपुरी नाला मास्टर प्लान से बाहर कैसे हुआ? ग्वालियर से भोपाल तक मचा हड़कंप

मास्टर प्लान 2035 से गायब हुआ चेतकपुरी नाला प्रोजेक्ट को लेकर अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी

ग्वालियर के पॉश इलाके में चेतकपुरी नाले को मास्टर प्लान 2035 से गायब करने पर भोपाल तक मचा बवाल, दोषी अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पॉश इलाके चेतकपुरी रोड के किनारे नाले और जलस्रोत को मास्टर प्लान से गायब कर वहां कॉलोनियां बसाने के एक बड़े और बहुचर्चित मामले में अब शासन स्तर पर कड़ी कार्रवाई की गाज गिरनी तय हो गई है। ग्वालियर के स्थानीय अधिकारियों और बिल्डरों की इस मिलीभगत और बड़े कारनामे पर अब शासन ने पूरी तरह मुहर लगा दी है, जिससे भोपाल तक हड़कंप मच गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) के आयुक्त सह संचालक को पत्र जारी कर इस क्षेत्र में दी गई सभी त्रुटिपूर्ण विकास अनुज्ञाएं यानी अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस गंभीर गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाने वाले दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी तत्काल भेजने को कहा गया है। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब गत मई माह में नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य शासन सचिव (एसीएस) संजय दुबे ग्वालियर के दौरे पर आए थे। उनके निरीक्षण के दौरान चेतकपुरी स्थित नाले के आसपास कॉलोनियां कटती हुई पाई गईं और मौके पर नाले का प्रवाह क्षेत्र भी बदला जा रहा था। इस भारी अनियमितता को देखकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की और तुरंत सारी फाइलें तलब कर ली थीं, जबकि इस संबंध में लोकायुक्त और न्यायालय में भी प्रकरण पहले से विचाराधीन हैं। इसके बाद दो जुलाई को संयुक्त संचालक टीएंडसीपी केएस गवली को भोपाल तलब किया गया और मास्टर प्लान की विस्तृत



जानकारी मांगी गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मास्टर प्लान 2005 के रंगीन मानचित्र पर यह जलस्रोत स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था लेकिन पैनल मानचित्र में दर्ज था, और मास्टर प्लान 2021 के रंगीन नक्शे में भी यह जलप्रवाह स्रोत पूरी तरह अंकित था, जिसे शातिराना तरीके से मास्टर प्लान 2035 के नक्शे से ही गायब कर दिया गया। इस खुलासे के बाद नगरीय प्रशासन विभाग की अवर सचिव सुप्रिया पेंडके द्वारा आयुक्त सह संचालक टीएंडसीपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ग्वालियर के पुराने मास्टर प्लान 2021 के आधार पर चेतकपुरी नाले अथवा जलप्रवाह स्रोत को मास्टर प्लान 2035 के पैनल मानचित्र पर यथावत पुनः अंकित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस नाले के रेखांकन क्षेत्र में भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई विकास अनुज्ञा जारी न की जाए और जिला कार्यालय द्वारा इस क्षेत्र में पहले से जारी की गई सभी त्रुटिपूर्ण विकास अनुज्ञाओं को निरस्त करने के लिए शासन को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा जाए। विभाग ने मास्टर प्लान 2035 से नाले को हटाने की इस साजिश में शामिल और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव एक माह के भीतर शासन को प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि चेतकपुरी जलस्रोत के आसपास पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल छह विकास अनुज्ञाएं जारी की गई थीं, जिनके आधार पर नगर निगम ने भी धड़ल्ले से प्लाटिंग और निर्माण की अनुमतियां जारी कर दी थीं। इनमें विद्युत गृह निर्माण समिति के सुरेंद्र सिंह भदौरिया के नाम पर तीन विकास अनुज्ञाएं, दीपक सचेती के नाम पर एक विकास अनुज्ञा, परिकल्प रियलिटी के राकेश शर्मा के नाम पर एक और अर्जुन कपूर के नाम पर एक विकास अनुज्ञा शामिल है, हालांकि नाले का रुख मोड़े जाने के कारण अर्जुन कपूर की विकास अनुज्ञा पहले ही निरस्त की जा चुकी है। शासन का मानना है कि बायपास तक की हद में ऐसे कई अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं, जो जलस्रोत के दायरे में होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ी के साथ जारी किए गए थे, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।

मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू: अश्विन मास में अब तेज धूप और उमस दिखाएगी तेवर

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



हिंदू पंचांग के अनुसार पवित्र अश्विन मास (क्वार का महीना) शुरू हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश के अंचल से मानसून अब अपनी विदाई की अंतिम बेला में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर मानसून इस क्षेत्र से पूरी तरह विदा हो जाएगा। आसमान से काले बादलों के छंटने और मौसम के बिल्कुल साफ हो जाने के कारण अब धरती पर सीधे धूप का राज रहेगा, जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मानसून के जाने के बाद बादलों की गैरमौजूदगी और हवा में नमी बरकरार रहने के चलते तेज धूप के साथ-साथ उमस भरी गर्मी लोगों को खासा परेशान करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी तीन से चार दिनों तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में वर्षा के दूर-दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मौसमी सिस्टम सक्रिय हुआ भी है, वह मध्य प्रदेश के इस अंचल तक पहुंचते-पहुंचते अत्यधिक कमजोर हो जाएगा, जिससे बारिश की उम्मीद लगभग नगण्य है। मौसम के इस बदलते मिजाज और संक्रमण काल के चलते दोपहर के समय चिलचिलाती धूप और चिपचिपी उमस का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियात बरतने और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है।

सागर में अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए राहत भरी खबर

ट्रस्ट ने की ठहरने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के सागर जिले में आगामी 1 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। दूर-दराज के जिलों से आने वाले इन युवाओं की मदद के लिए समाजसेवी एवं महात्मा पूरण दास ट्रस्ट, मगरोनी के अध्यक्ष जंडेल सिंह गुर्जर ने आगे बढ़कर सागर रेलवे स्टेशन से लेकर युवाओं के ठहरने, भोजन और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस सराहनीय पहल से भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने आने वाले युवाओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी और उन्हें बाहरी शहरों में रहने-खाने की चिंता नहीं सताएगी। इस महत्वपूर्ण अग्निवीर सेना भर्ती रैली में सागर के अलावा शिवपुरी, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर समेत



कुल 10 जिलों के करीब 11 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जंडेल सिंह गुर्जर ने जानकारी दी है कि विगत वर्षों की तरह इस बार भी भर्ती में आने वाले युवाओं को सागर रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों के ठहरने और भोजन की पुख्ता व्यवस्था शहर के मकरोनिया स्थित शिव पार्वती गार्डन में की गई है, जहाँ नाश्ते, भोजन और फोटोकॉपी जैसी तमाम जरूरतें निशुल्क पूरी की जाएंगी।

ग्वालियर में सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव: बैरिकेडिंग गिराई

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों की संख्या ??? कार्यकर्ता जिला न्यायालय गेट पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली, जहां कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को भी गिरा दिया।प्रदर्शन की उग्रता को भांपते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि, उग्र नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर गिरा दिए और कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर घुसने का प्रयास किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को परिसर में आगे जाने से रोक दिया। इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की अपेक्षा होती है, लेकिन ज्ञानेश कुमार पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लग रहे हैं।

ग्वालियर में भूटानी डॉग्स को बनाया जा रहा एक्सपर्ट नारकोटिक्स से विस्फोटक तक खोजने का प्रशिक्षण

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



बीएसएफ अकादमी टेकनपुर का राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र अब देश ही नहीं, विदेश के सुरक्षा बलों के कुत्तों को भी प्रशिक्षित कर रहा है। यहां भूटान के सुरक्षा बलों के बेल्जियन मेलिनोइस कुत्ते प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके साथ आए हैंडलर भी बीएसएफ के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के कुत्ते भी यहां प्रशिक्षणरत हैं। देश में बीएसएफ अकादमी ही ऐसी है, जहां राष्ट्रीय स्तर का श्वान प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहा है। नारकोटिक्स से बम डिटेक्शन तक प्रशिक्षण केंद्र में कुत्तों को नारकोटिक्स, बम डिटेक्शन सहित अलग-अलग विधाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। भूटान के कुत्ते पहले भी बीएसएफ अकादमी के प्रशिक्षित हैंडलरों से ट्रेनिंग ले चुके हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के कुत्ते भी यहां पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं। सुरक्षा बलों की मांग के आधार पर विभिन्न नस्लों के कुत्तों को संबंधित जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र में प्रजनन केन्द्र संचालित प्रजनन केंद्र में देसी-विदेशी नस्लों पर काम राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में प्रजनन केंद्र भी संचालित है। यहां देसी और विदेशी दोनों नस्लों के कुत्तों का प्रजनन कराया जाता है। जन्म के बाद से ही कुत्तों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे आगे चलकर विभिन्न प्रशिक्षण विधाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

सीएनजी कार चालकों के लिए बड़ी खबर:

बिना 'हाइड्रो टेस्ट' सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी गैस, रीफिलिंग के कड़े नियम लागू

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

यदि आप भी सीएनजी कार का इस्तेमाल करते हैं और अब तक अपने वाहन में लगे गैस सिलेंडर का 'हाइड्रो टेस्ट' नहीं करवाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम उठाते हुए अब सीएनजी पंपों पर गैस रीफिलिंग के नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बिना वैध हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट के सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों में गैस मिलना लगभग बंद हो जाएगा। सुरक्षा कारणों से लिया गया बड़ा फैसला पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन और देश की विभिन्न गैस वितरण कंपनियों के तय नियमों के अनुसार, वाहन चालकों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सख्त निर्णय लिया गया है। सीएनजी सिलेंडरों के भीतर गैस अत्यधिक उच्च दबाव पर भरी जाती है। लंबे समय तक गाड़ी चलाने और इस्तेमाल के कारण सिलेंडरों के अंदरूनी हिस्से में जंग लगने, दरारें आने या धातु के कमजोर होने का खतरा बना रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिना तकनीकी जांच



और वैध प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों में गैस रीफिल करना सड़क पर चलते-फिरते एक बड़े खतरे को खुला बुलावा देने जैसा है। हर 3 साल में हाइड्रो टेस्ट कराना अनिवार्य वाहन विशेषज्ञों और सुरक्षा मानकों के मुताबिक, प्रत्येक सीएनजी वाहन मालिक के लिए अपने सिलेंडर का हर 3 साल में कम से कम एक बार हाइड्रो टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सिलेंडर को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और उसे किसी अधिकृत टेस्टिंग सेंटर पर भेजा जाता है। वहां पानी के भारी दबाव के जरिए सिलेंडर की मजबूती, उसकी सहनशक्ति और सुरक्षा स्थिति की बारीकी से जांच की जाती है। सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित और मानक के अनुकूल पाए जाने पर ही इसका अधिकृत सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ग्वालियर और पूरे अंचल में इन दिनों बड़ी संख्या में सीएनजी वाहनों का संचालन हो रहा है। हझालांकि, जानकारी के अभाव या अनदेखी के चलते कई वाहन मालिक वर्षों तक बिना किसी टेस्टिंग के ही अपनी गाड़ियां धड़ल्ले से चला रहे हैं। लेकिन अब पंपों पर शुरू होने वाली सख्ती के चलते ऐसे लापरवाह चालकों को रीफिलिंग न होने पर बिना गैस के ही बैरंग लौटना पड़ सकता है। वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अपने नजदीकी अधिकृत सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग सेंटर पर जाएं।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड

चीनी तीरंदाजों को हराया

ओकाजाकी । एशियन गेम्स 2026 में बुधवार को भारतीय दल का आर्चरी में स्वर्णिम सफर जारी है। भारतीय आर्चरी टीम ने तीसरा गोल्ड जीत लिया है। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु वाली भारतीय पुरुषों की



कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की तिकड़ी ने एक रोमांचक फाइनल में चीन के जियाओ लियाओ, जिनयी लियू और जिंग्यू शी को 238-237 से हराकर भारत के कंपाउंड तीरंदाजों के लिए गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की। यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत फाइनल में दो पॉइंट से पीछे था और चीन की बढ़त को खत्म करने के लिए उसे एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी।

कपिल पोखरिया को करना पड़ा ब्रॉन्ज मेडल से संतोष

सेमीफाइनल में मिली हार

निशियो । एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष मुक्केबाज कपिल पोखरिया को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। कपिल को 90 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के तुरबेक खबीबुल्लाव के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में कपिल तुरबेक के सामने संघर्ष करते नजर आए



और फाइनल में जगह बनाने का उनका सपना साकार नहीं हो सका। हालांकि, वह अपने एशियन गेम्स डेब्यू में ही ब्रॉन्ज मेडल जीतने में जरूर सफल रहे। तुरबेक ने शुरुआत से ही मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी और पहले राउंड को 5-0 से जीता। इसके बाद दूसरे राउंड में भी उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज का दबदबा देखने को मिला और वह राउंड को 4-1 से अपने नाम करने में सफल रहे।

गुलवीर ने लगाई मेडल की हैट्रिक, 5000 मीटर दौड़ में जीता ब्रॉन्ज

नागोया । गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रचते हुए मेडल की हैट्रिक पूरी कर ली है। भारतीय धावक ने मंगलवार को मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में पुरुषों की 5000 मीटर



दौड़ के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। गुलवीर ने इस रेस को 13:32.75 सेकंड में पूरा किया। बहरीन के बिरहानु बालेव ने 13:30.79 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि जापान के यामागुची टोमोनोरी 13:31.43 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

श्री चरणी ने रच दिया इतिहास

आईसीसी विमेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड



दुबई । भारत की श्री चरणी ने आईसीसी विमेंस टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद बाएं हाथ की स्पिनर अपने करियर के बेस्ट 817 प्वाइंट्स तक पहुंच गई। श्री चरणी पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में 'वर्ल्ड नंबर-1' गेंदबाज हैं। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के (806 रेटिंग प्वाइंट्स) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसे मेगन ने नवंबर 2018 में बनाया था। चरणी ने भारत की सफल यात्रा में अहम भूमिका निभाई और एशियन गेम्स में अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए भारत को अपना गोल्ड मेडल बचाने में मदद की। एशिया कप 2026 में श्री चरणी ने 12 विकेट लेकर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे।

श्री चरणी ने एशियन गेम्स 2026 में जापान के खिलाफ 10/4 का अपना करियर-बेस्ट प्रदर्शन करते हुए भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में मदद की थी। खिताबी मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत ने यह मैच 147 रन से जीतकर गोल्ड मेडल जीता।



एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के विरुद्ध 6 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने 754 प्वाइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स के फाइनल में 79 रन की पारी खेली थी, जिसके साथ उन्होंने टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी की रैंकिंग में टॉप-5 में वापसी कर ली है।

दूसरी ओर, हरारे में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच जारी सीरीज ने वनडे फॉर्मेट में काफी बदलाव किया है। यह सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। वेस्टइंडीज की ऑल-राउंडर हेली मैथ्यूज ने सीरीज के पहले मैच में 182 रनों की दमदार पारी खेली थी, जिसके बाद वह 711 प्वाइंट्स के साथ बैटिंग रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गईं। उनकी साथी रियलीना ग्रिमंड 34 पायदान ऊपर चढ़कर 270 प्वाइंट्स के साथ संयुक्त रूप से 102वें स्थान पर पहुंच गईं।

इस बीच, जिम्बाब्वे की न्याशा ग्वांजुरा ने वनडे बॉलिंग रैंकिंग में एक अहम स्थान हासिल किया; उन्होंने दूसरे वनडे में 18 रन बनाने के साथ 4 विकेट हासिल किए। इस तरह वह 52 पायदान ऊपर चढ़कर 156वें स्थान पर पहुंच गईं।

महिला तीरंदाजी टीम ने रचा इतिहास

वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, गोल्ड जीता

राजेश-चिकिथा ने मिक्स्ड कंपाउंड टीम इवेंट में जीता गोल्ड



आइची-नगोया (जापान)। एशियन गेम्स 2026 में बुधवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्णिम शुरुआत लेकर आया। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने असाधारण और अचूक निशानेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए देश की झोली में 7वां स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) डाल दिया। महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने मजबूत प्रतिद्वंद्वी चीन को 238-234 के अंतर से पराजित किया।

ओलंपिक 2028 का टिकट भी हुआ पक्का

ओकाजाकी । एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम ने गोल्ड पर निशाना लगाया है। महिला टीम के गोल्ड जीतने के बाद राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को एक रोमांचक शूट-ऑफ में हराया। फाइनल में मुकाबला 157-157 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद भारतीय जोड़ी ने शूट-ऑफ में साउथ कोरिया के पार्क जुंगयून और चोई योंगही को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट का कोटा भी हासिल कर लिया है। यह इवेंट पहली बार ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। इससे पहले, महिला टीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद, यह चिकिथा का आइची-नागोया में दूसरा गोल्ड है। एशियन गेम्स



2026 में यह भारत का आठवां गोल्ड है। कुल मिलाकर, भारत के मेडल अभी 54 हैं, जिसमें आठ गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चिकिथा और साहिल ने शानदार शुरुआत की, दोनों तीरंदाजों ने अपने शुरुआती शॉट में 10-रिंग हासिल की। ??शुरुआती रोटेशन के बाद कोरियाई खिलाड़ियों ने उनकी बराबरी करते हुए स्कोर 20-20 कर दिया।

इसके बाद भारत को पहला फायदा तब मिला जब पार्क ने 9 का स्कोर किया। चिकिथा और साहिल ने 10 की एक और जोड़ी के साथ जवाब दिया और पहले एंड के आखिर में 40-39 से आगे हो गए। भारतीय जोड़ी ने दूसरे एंड में भी बेहतरीन निशाने लगाए और अपनी बढ़त दो अंक तक बढ़ा ली। चिकिथा और साहिल ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती चारों शॉट में 10-10 अंक हासिल किए।

लवलीना रोमांचक मुकाबले में नताल्या बोगदानोवा को हराकर फाइनल में पहुंचीं

ओकाजाकी । भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान की मुक्केबाज नताल्या बोगदानोवो को स्प्लिट फैसले में 3-2 से हराया। इस जीत के साथ ही लवलीना ने एशियन गेम्स 2026 में कम से कम अपना सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। हालांकि, भारतीय मुक्केबाज से देश को गोल्ड मेडल की आस है। लवलीना लगातार दो एशियन गेम्स में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। फाइनल मुकाबले में लवलीना ने जबरदस्त वापसी की। पहले राउंड में लवलीना लय में दिखाई नहीं दीं और उन्हें यह राउंड 2-3 से गंवाना पड़ा। हालांकि, इसके बाद भारतीय मुक्केबाज ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसका असर उनके खेल में भी नजर आया। लवलीना ने दूसरा और फिर तीसरा राउंड अपने नाम किया। लवलीना के एक के बाद दमदार पंचों के आगे कजाकिस्तान की महिला मुक्केबाज मुश्किल में दिखाई दी। दूसरे राउंड में लवलीना को पांच जजों की ओर से 10-10



प्वाइंट मिले। वहीं, तीसरे राउंड में दो जज ने लवलीना को 10, जबकि तीन जजों ने 9 प्वाइंट दिए। हालांकि, भारतीय महिला मुक्केबाज प्रिया घंघस को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। उन्हें सेमीफाइनल में चीन की यांग चेंग्यू के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। प्रिया सेमीफाइनल मैच में लय में दिखाई नहीं दीं और उनके पास चीन की मुक्केबाज के पंचों का कोई जवाब नहीं था। प्रिया ने मुकाबले की शुरुआत जरूर आक्रामक अंदाज में की, लेकिन यांग चेंग्यू का डिफेंस काफी मजबूत नजर आया। पुरुष भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं, नरेंद्र ने सेमीफाइनल मैच हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। नरेंद्र को सेमीफाइनल में ओरलबे ने एकतरफा अंदाज में 0-5 से हराया। महिला मुक्केबाज परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच चुकी हैं।

नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप शूटिंग इवेंट में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल

ओकाजाकी । एशियन गेम्स 2026 में बुधवार को भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल आया है। शूटिंग के मिक्स्ड ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को इस टूर्नामेंट का 9वां गोल्ड मेडल दिलाया। नीरू और किनान की जोड़ी ने 34 प्वाइंट्स अर्जित करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं, कतर ने 32 प्वाइंट्स हासिल करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि चीन 23 प्वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहा। ईरान फाइनल में 12 प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर रहा। नीरू का यह एशियन गेम्स 2026 में तीसरा मेडल है। इससे पहले, नीरू ने महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर



मेडल जीता था। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वह ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनीं। मिक्स्ड ट्रैप इवेंट के फाइनल में नीरू और किनान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली सीरीज में 6 प्वाइंट हासिल किए, जबकि दूसरी सीरीज में यह भारतीय जोड़ी 16 प्वाइंट अर्जित करने में कामयाब रही। तीसरी सीरीज के अंत तक भारत ने 26 प्वाइंट हासिल किए और चौथी और आखिरी सीरीज में स्कोर को 34 पर पहुंचाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

बुधवार को यह भारत ने तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले, आर्चरी के मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी की जोड़ी ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने रोमांच से भरपूर फाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया को शूट-ऑफ में हराया।



महिला 4X400 मीटर रिले टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक पर

प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण पहल, एमआर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विथ्या रामराज को मंगलवार को एशियाई खेलों में महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। कड़े मुकाबले वाले फाइनल में भारतीय टीम ने 3:29.69 का समय निकालकर बहरीन (3:30.21) और चीन (3:31.02) को पीछे छोड़ दिया, जिससे भारत ने एशियाई खेलों में महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक का लंबा इंतजार खत्म किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एशियाई खेलों में महिला 4×400 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन के लिए किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज को हार्दिक बधाई। उनकी गति और दृढ़ संकल्प ने भारत को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का क्षण है और टीम वर्क की उपलब्धियों का एक बेहतरीन उदाहरण है! खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

फाइनल में भारत ने छठे लेन से शुरुआत की, जिसमें किरण ने पहला लेग दौड़ा और फिर तीसरे स्थान पर अनुभवी पूवम्मा को बैटन सौंपा। पूवम्मा ने दूसरे लेग में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को शीर्ष स्थान पर ला खड़ा किया।

प्राची ने भारत को पदक की दौड़ में बनाए रखा और फिर एंकर लेग के लिए बैटन विथ्या को सौंप दिया।

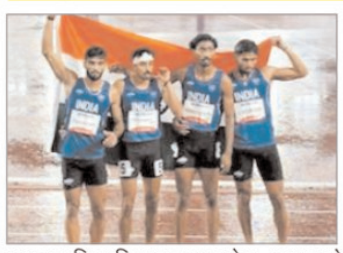
विथ्या ने शानदार फिनिशिंग करते हुए 200 मीटर के निशान के पास अपनी बढ़त बनाई और अंतिम क्षणों में बहरीन की सलवा ईद नस्र को पछाड़कर भारत के लिए स्वर्ण पदक पक्का किया। यह जीत एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में महिलाओं की 4×400 मीटर रिले में भारत के रजत पदक से कहीं बेहतर प्रदर्शन था।



विथ्या के लिए भी यह खेल यादगार रहा, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना तीसरा पदक जीता। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में रजत और कांस्य पदक जीते थे और रिले फाइनल से एक दिन पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा था। जापान 3:31.44 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहा, उसके बाद वियतनाम, कजाकिस्तान, श्रीलंका और चीनी ताइपे रहे।

भारतीय पुरुषों ने 4X400 मीटर रिले में जीता ब्रॉन्ज

कुल 24 मेडल के साथ एथलेटिक्स में अभियान समाप्त



नागोया। भारत ने मंगलवार को पुरुषों की 4×400 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल के साथ 'एशियन गेम्स 2026' में अपने एथलेटिक्स अभियान का समापन किया। मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में धर्मवीर चौधरी, मनु थीक्किनिल, जय कुमार और विशाल थेन्नारासु की भारतीय चौकड़ी ने 3:01.61 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। जापान ने 3:00.75 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कतर ने 3:00.93 के समय के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत चैंपियन टीम से 0.86 सेकंड पीछे रहा। फाइनल में धर्मवीर ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई और मनु को बैटन सौंपी, तब तक टीम मेडल की दौड़ में मजबूती से बनी हुई थी। दूसरे लेग के दौरान मनु को भीड़ का सामना करना पड़ा और उन्हें ट्रैक पर अपनी जगह बनाने के लिए घूमना पड़ा, जिससे जब जय कुमार ने दौड़ संभाली तो भारत चौथे स्थान पर था।

संक्षिप्त समाचार

चाय के खर्च में शुरू करें निवेश और कमाएं 25% तक मुनाफा! देखें टॉप 5 फंड्स

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में निवेश के कई सारे विकल्प हैं, जहां लोग पैसे लगाकर एक समय के बाद अच्छी कमाई करते हैं। इस बीच हम यहां बात



म्यूचुअल फंड एसआईपी की कर रहे हैं। एसआईपी जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, यह निवेश का एक ऐसा जरिया है, जहां तय राशि के साथ तय समय पर लगातार निवेश किया जाता है, जिसमें आप खासकर के लंबी अवधि में अच्छा-खासा पैसा बना लेते हैं। हम यहां ऐसे ही पांच इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लंबी अवधि में 19.8 प्रतिशत से लेकर 24.6 प्रतिशत (करीब 25%) तक का रिटर्न दिया है। इसमें आप हर महीने का निवेश चाय के खर्च में भी शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक चाय की कीमत कम से कम 10 रुपये है, अगर आप हर रोज भी एक चाय पीते हैं तो एक महीने में करीब 300 रुपये हो जाएंगे। लेकिन, यहां कम से कम 100 रुपये महीने से ही एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब आइए इन पांच फंड्स और इनके रिटर्न के बारे में जानते हैं। क्वांट श्वरूस्-टैक्स सेवर की बात करें तो इसमें आप कम से कम 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी अभी की नेट एसेट वैल्यू 117.89 रुपये है। इसने बीते 10 साल में 19.8 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यूनियन स्मॉल कैप ने 10 साल में कितना रिटर्न दिया है यूनियन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने 10 साल में अपने एसआईपी निवेशकों को 20 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसमें कम से कम आप 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसकी अभी की 66.09 रुपये है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में आप कम से कम 100 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी अभी की एनएवी 232.6 रुपये है।

8वें वेतन आयोग से सिविलियन पेंशनर्स क्यों मांग रहे हैं 'वन रैंक, वन पेंशन'

नईदिल्ली, एजेंसी। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं। इनमें एक प्रमुख मांग वन रैंक, वन पेंशन लागू करने की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक ही पद या स्तर से अलग-अलग समय पर रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। वन रैंक, वन पेंशन यानी मूल उद्देश्य समान पद और समान सेवा अवधि वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच पेंशन की असमानता को कम करना है। मौजूदा व्यवस्था में अलग-अलग वेतन आयोगों के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अलग हो सकती है। इसका कारण यह है कि समय के साथ सैलरी और पेंशन तय करने के नियम बदलते रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2015 में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लागू किया था, जिसका वित्तीय लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी माना गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए भी अलग पेंशन समानता व्यवस्था मौजूद है। अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसी तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार के लेवल 1 से 18 तक के नागरिक कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाए। के. सी. श्रीकुमार के अनुसार, पुराने वेतन आयोगों ने भी पुराने और नए पेंशनर्स के बीच पेंशन के अंतर को कम करने की जरूरत पर चर्चा की थी। 5वें वेतन आयोग ने 1986 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन को 1 जनवरी 1986 के आधार पर वेतन तय करके अपडेट करने का सुझाव दिया था। इसके लिए सेवारत कर्मचारियों पर लागू वेतन निर्धारण के फॉर्मूले को आधार बनाने की बात कही गई थी। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि संबंधित पद के संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का 50 फीसदी से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए।

अल्ट्राटेक ने ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अपनी पहली इंटीग्रेटेड यूनिट के साथ हासिल की डिकार्बनाइजेशन की बड़ी उपलब्धि

एक सत बुलेटिन, रायपुर



अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जो चीन को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, ने डीकाबोर्नाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ स्थित, कंपनी की एकीकृत सीमेंट विनिर्माण इकाई कुकुरडीह सीमेंट वर्क्स अप्रैल 2026 से लगातार हर माह अपनी 100 प्रतिशत विद्युत आवश्यकता हरित ऊर्जा स्रोतों से पूरी कर रही है।

वर्ष 2024 में कमीशन किए गए कुकुरडीह सीमेंट वर्क्स की स्थापित ग्रे सीमेंट उत्पादन क्षमता 3.3 मिलियन टन प्रति वर्ष है। संयंत्र ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम (हल्फर) के प्रभावी समन्वय से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन हरित ऊर्जा स्रोतों से अब संयंत्र की संपूर्ण विद्युत आवश्यकता पूरी हो रही है, साथ ही परिचालन की विश्वसनीयता भी पूरी तरह बरकरार है। अप्रैल 2026 से, अल्ट्राटेक की भारत में स्थित 76 विनिर्माण इकाइयों में से लगभग एक-तिहाई इकाइयां अपनी कुल विद्युत आवश्यकता का 50% से अधिक हिस्सा हरित ऊर्जा से पूरा कर रही हैं। इनमें कुकुरडीह सीमेंट वर्क्स सहित पांच इकाइयों में हरित ऊर्जा का उपयोग 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। अल्ट्राटेक अक्षय ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देने के लिए, अपने नेटवर्क में चरणबद्ध रूप से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (इएरर) भी स्थापित कर रही है। अल्ट्राटेक ने, डीकाबोर्नाइजेशन की अपनी नीति और परिचालन में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, पिछले दस वर्षों से अधिक समय से अपनी एकीकृत इकाइयों में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं अथवा ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए नई कैप्टिव थर्मल पावर क्षमता में निवेश नहीं किया है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (द1ऋ27) तक कंपनी की कैप्टिव हरित ऊर्जा क्षमता 1,897 मेगावाट थी, जिसमें 1,463 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता (सौर, पवन एवं हाइब्रिड) तथा 434 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम (हल्फर) क्षमता शामिल है। अपनी ह्यफ्ए100ह्ल प्रतिबद्धता के तहत अल्ट्राटेक ने अपने कुल ऊर्जा मिश्रण में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 85% और वर्ष 2050 तक 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऑयल सप्लाई युद्ध पूर्व स्तर के करीब पर कीमत अब भी 100 के पार, कहां डबल हुए डीजल के दाम

नईदिल्ली, एजेंसी। कच्चे तेल की मिडिल ईस्ट से सप्लाई युद्ध से पहले के स्तर के करीब पहुंच रही है। सऊदी अरब ने होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाली पाइपलाइन से तेल भेजना फिर शुरू कर दिया है। हालांकि, ब्रेंट क्रूड अब भी 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट 103 डॉलर के आसपास है। दूसरी ओर अमेरिकी बेंचमार्क पिछले सत्र में 3.5% गिरने के बाद 89 डॉलर प्रति बैरल की ओर फिसल गया है। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 30 सितंबर के पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। क्रूड के 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बने रहने से दुनिया के कई देश पेट्रोल-डीजल की महंगाई से जूझ रहे हैं। ईरान युद्ध के बाद से अबतक लेबनान और नाइजीरिया में डीजल की कीमत में 104 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ग्लोबलपेट्रोलप्राइसेज डॉट कॉम पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इंडोनेशिया, पनामा, बोलीविया और ग्वाटेमाला में डीजल के दाम करीब 81 से 87 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। सप्लाई युद्ध से पहले के स्तर का 98% पर जेपी मॉर्गन की नताशा कानेवा की टीम के मुताबिक, मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का निर्यात बढ़कर 17.5 मिलियन बैरल रोज हो गया है। यह युद्ध से पहले के स्तर का 98% है।

एनपीएस में रिस्क क्षमता देखकर मिलेगी स्कीम, नया प्लैटफॉर्म लाने की तैयारी



नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन प्रोडक्ट्स को लेकर नियम-कायदों के सुरक्षा घेरे मजबूत करने और ग्राहकों को बेहतर विकल्प देने के मकसद से पेंशन फंड नियामक एक सूटेबिलिटी प्लैटफॉर्म लाने की तैयारी कर रहा है। यह प्लैटफॉर्म (नैशनल पेंशन सिस्टम) सब्सक्राइबर्स की जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करेगा और स्कीम चुनने से पहले उनसे इससे जुड़े जरूरी सवाल पूछेगा।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एस. रमण ने कहा, हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रोडक्ट ग्राहक की जरूरत के हिसाब से हो और उसकी रिस्क लेने की क्षमता का पता चले। चाहे प्लैटफॉर्म हो या ट्रस्ट का प्लैटफॉर्म, हर जगह सब्सक्राइबर्स से सही सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि, स्कीम का आखिरी चुनाव उनका अपना ही होगा। लेकिन हमारा काम उनकी रिस्क क्षमता को बेहतर तरीके से समझना और तय करना है।

रमण ने कहा कि ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से सही विकल्प देने का एक जरिया लाइफसाइकल प्रोडक्ट्स भी हैं। रिस्क ऐपेटाइट के आधार पर चार लाइफसाइकल ऑप्शन उपलब्ध हैं। इनमें जैसे-जैसे सब्सक्राइबर की उम्र बढ़ती है, पैसों का निवेश अपने आप बदल जाता है। एक स्टडी के मुताबिक, भारतीयों की औसत उम्र बढ़ रही है और यह 78 साल तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ औसतन परिवार का आकार घटकर 4.4 सदस्यों का रह गया है। इसके बावजूद, देश में पेंशन का दायरा अभी भी 17 से 18 फीसदी के निचले स्तर पर बना हुआ है। अध्ययन के मुताबिक, रिटायरमेंट के लिए एनपीएस को गंभीरता से चुनने वाले लोगों का आंकड़ा 2023 के मुकाबले 6 पॉइंट बढ़कर 59 पर पहुंच गया है। वहीं, बचत के मुख्य कारणों में बच्चों की पढ़ाई का स्थान अब इमरजेंसी सेविंग्स ने ले लिया है।

ईपीएफ सीमा का असर

रमण ने कहा कि की सीमा बढ़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, कर्मचारी इस सीमा के बाद भी अन्य विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। एस. रमण ने बताया कि लंबी अवधि के निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जरूरत होती है और कम से कम 15 साल तक निवेशित रहने वालों को इक्विटी से काफी फायदा मिलता है। निवेश का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी शामिल कर लिया है।

दुनिया को पड़ सकते हैं खाने के लाले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया आगाह, आने वाला है बहुत संकट

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान और यूक्रेन युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बड़े संकट के प्रति दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ईरान और यूक्रेन युद्धों के कारण दुनिया में उर्वरक की कमी हो गई है। इससे आने वाले दिनों में एक बड़ा खाद्य संकट आ सकता है। उन्होंने कहा कि खासकर ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। भारत भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है।

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 'एशिया सोसाइटी' में कहा, 'यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। अगर आप इन दोनों युद्धों यूक्रेन और अब ईरान-खाड़ी संघर्ष को देखें, तो इनका ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है।' ग्लोबल साउथ का मतलब उन विकासशील और अल्प विकसित देशों से है जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में स्थित हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि ऊर्जा की स्थिति को लेकर खास चिंता है, क्योंकि बाजार में आपूर्ति बहुत कम है और ऊपर से, अगर लोग इस पर राजनीति करते हैं, तो इससे बाजार में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इससे कीमतें उस वक्त बढ़ेंगी, जब असल में लोगों को कीमतों को स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में उर्वरक की भारी कमी हो सकती है, क्योंकि इसके मुख्य उत्पादक देश पश्चिम एशिया और रूस हैं और वहां उर्वरक



के उत्पादन पर असर पड़ा है।

जयशंकर ने कहा, 'तो इसका एक हिस्सा असल में तेल की आपूर्ति की सुरक्षा से जुड़ा है, और दूसरा हिस्सा तेल की आपूर्ति की राजनीति से। ये दोनों एक-दूसरे पर असर डाल रहे हैं और एक दोहरा संकट या और गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं। आज हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जिसमें अनाज के कुछ बड़े निर्यातक देश अपनी खेप नहीं भेज पाएंगे, खासकर काला सागर मार्ग से।'

सुपर अल नीनो जैसे मौसम के पैटर्न के असर का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, 'आगामी महीनों में शायद एक बड़ा खाद्य संकट आ सकता है। तो अगर ऊर्जा की भारी कमी हो, और उसके साथ ही खाद्यान्न और उर्वरक की भी कमी हो, और साथ में वित्तीय समस्या भी हो - क्योंकि जब भी कोई टकराव होता है, तो पैसा सुरक्षित जगहों की तरफ चला जाता है और 'ग्लोबल साउथ' से दूर हो जाता है - तो इन सबका कुल नतीजा बहुत तनावपूर्ण रहा है।' उन्होंने कहा कि नीति बनाने वाले यह नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति पैदा करने का उनका इरादा नहीं था। जयशंकर ने कहा, 'देशों को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वे अपने फैसले लें और फिर कहें कि 'मेरा मकसद आपका जीवन मुश्किल बनाना नहीं था।'

यूक्रेन युद्ध: जयशंकर ने कहा कि समझदारी से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बहुत सारे देशों की बुनियादी जरूरतों को इतना नजरअंदाज न किया जाए कि वे मुश्किल हालात में फंस जाएं, और यही हमारी चिंता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट अस्थिरता पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हमने यूक्रेन युद्ध के बाद पहले ही यह देख लिया है। हमने अपने पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता के रूप में इसका सीधा असर देखा है, और मुझे डर है कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो हो रहा है, उससे यह स्थिति और बिगड़ेगी।'

अमेरिका में ज्यादा ऑप्शन थे, लेकिन...' नौकरी छोड़ भाई के साथ अपना काम, आज 25 करोड़ की कंपनी के मालिक

नई दिल्ली, एजेंसी। यह कहानी है अहमदाबाद के दो भाइयों की। इनके नाम हैं अतीश शाह और आशील शाह। निजी जरूरत के अनुभव से उन्हें आइडिया मिला। इसे भाइयों ने सफल बिजनेस में तब्दील कर दिया। उनके स्टार्टअप का नाम 'पोल्का टॉट्स' है। यह ब्रांड नवजात शिशुओं से लेकर आठ साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, स्वैडल्स (बच्चों को लपेटने वाले मुलायम कपड़े) और रोजमर्रा के एसेंशियल्स बेचता है। आज इसका ग्रॉस टर्नओवर 25 करोड़ रुपये के पार निकल गया है। आइए, यहां अतीश शाह और आशील शाह की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

साल 2016 की बात है। आशील शाह के घर पहले बच्चे का आगमन होने वाला था। अमेरिका में रह रहे उनके भाई अतीश शाह भारत के लिए बेबी प्रोडक्ट्स की तलाश कर रहे थे। इस दौरान



उन्हें महसूस हुआ कि यह सेक्टर बेहद असंगठित है। बाजार में अच्छे ऑप्शंस की भारी किल्लत है। इसी व्यक्तिगत निराशा और खालीपन ने उन्हें आइडिया दिया। नौकरी छोड़कर उन्होंने भाई के साथ साल 2018 में अपने स्टार्टअप की नींव डाली। अतीश ने एक इंटरव्यू में कहा, 'अमेरिका में बेशक ज्यादा विकल्प थे। लेकिन, हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में प्रोडक्ट्स ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है। इसलिए हमने भारत में तलाश शुरू की। पाया कि यह सेक्टर पूरी तरह से असंगठित है।' शुरुआत में शाह भाइयों ने स्वैडल्स के सिर्फ 3 स्थह्य के साथ अमेजन पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की। वहां उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय माता-पिता के बीच नए और आधुनिक उत्पादों की जागरूकता पैदा करने की थी। सफेद कपड़ों या इस्तेमाल किए गए कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। इसे बदलने के लिए भाइयों ने ऑनलाइन तस्वीरों और वीडियो कंटेंट के जरिए उत्पादों की खूबियों को समझाना शुरू किया। शुरुआत में वे अपने 90% उत्पाद चीन से मंगाते थे। लेकिन, अपने कड़े डिजाइन स्टैंडर्ड्स और बेहतरीन क्वालिटी के दम पर उन्होंने धीरे-धीरे भारतीय बाजार में अपनी मजबूत जगह बनानी शुरू कर दी।

यू ट्यूब से कमाई का बढ़ा ट्रेंड, जीडीपी में 18000 करोड़ रुपये का योगदान, 9.6 लाख को मिला रोजगार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में यूट्यूब का क्रिएटर इकोसिस्टम तेजी से बड़ा आर्थिक क्षेत्र बनता जा रहा है। यूट्यूब की 2025 इम्पैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेटफॉर्म के क्रिएटिव इकोसिस्टम ने साल 2025 में भारत की जीडीपी में 18000 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान दिया। इसके साथ ही इस इकोसिस्टम ने 9.6 लाख से ज्यादा फुल-टाइम नौकरियों के बराबर रोजगार को सपोर्ट किया। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक इकोसिस्टम से सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को ही फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि सिनेमैटोग्राफर, साउंड इंजीनियर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोडक्शन से जुड़े प्रोफेशनल्स समेत कई तरह के क्रिएटिव और टेक्निकल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम का भारत की जीडीपी में योगदान पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इससे पहले के साल में इस इकोसिस्टम ने 16000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक योगदान दिया था और 9.3 लाख से अधिक फुल-टाइम नौकरियों के बराबर रोजगार को



सपोर्ट किया था।

यूट्यूब के मुताबिक, प्लेटफॉर्म का आर्थिक प्रभाव अब सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। जयपुर, लखनऊ और कोच्चि जैसे नॉन-मेट्रो शहरों में भी नए क्रिएटिव क्लस्टर उभर रहे हैं। इन शहरों में स्थानीय प्रतिभाओं को तकनीकी और प्रोफेशनल स्किल विकसित करने के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपना काम और कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन करने वाले क्रिएटर्स के इकोसिस्टम ने 3 लाख से ज्यादा अप्रेंटिस को सपोर्ट किया। इससे डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी में युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बढ़ने का संकेत मिलता है। भारत यूट्यूब का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। देश में प्लेटफॉर्म के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। यही वजह है कि भारत यूट्यूब के लिए वैश्विक स्तर पर ग्रोथ का एक बड़ा केंद्र है। कंपनी के मुताबिक, जून 2026 तक भारत में 20,000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुके थे।

भारतीय क्रिएटर्स की पहुंच अब सिर्फ घरेलू दर्शकों तक सीमित नहीं है। यूट्यूब के अनुसार, भारतीय चैनलों पर बनाए गए कंटेंट के कुल वॉच टाइम का 15% से ज्यादा हिस्सा देश के बाहर के दर्शकों से आता है। यह भारतीय क्रिएटर्स के कंटेंट की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाता है।

यूट्यूब ने बताया कि पिछले एक साल में भारत के 2 लाख से ज्यादा चैनलों ने पहली बार प्लेटफॉर्म से कमाई शुरू की। वहीं, सालाना 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कमाने वाले चैनलों की संख्या में साल-दर-साल 20% से अधिक की वृद्धि हुई। कमाई करने वाले क्रिएटर्स में से 73% ने यूट्यूब को अपनी आय का मुख्य स्रोत बताया है।

10 ग्राम सोने पर 10000 का डिस्काउंट! महंगे गोल्ड के बीच बढ़ा कैश का खेल, बिना रसीद के बिक रहे गहने

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद इसकी कीमतें अब भी काफी ऊंचे स्तर पर हैं। करीब एक साल पहले के मुकाबले सोना लगभग 28% महंगा है। ऐसे में ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों के बीच सस्ता सोना पाने के लिए कैश में बिना बिल खरीदारी का चलन बढ़ने की खबर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खरीदार आधिकारिक सिस्टम से बाहर जाकर बिना रसीद के सोना और ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी मात्रा में सोना खरीदने पर अनौपचारिक कैश डील के जरिए मौजूदा बाजार कीमत से करीब 6% तक कम कीमत मिल सकती है। यह डिस्काउंट प्रति 10 ग्राम सोने पर 10 हजार रुपये तक हो सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार, कैश में लेनदेन करने वाले कुछ डीलर टैक्स और अन्य लागत से बचने का फायदा ग्राहकों के साथ साझा करते हैं। 55 साल की एक महिला ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदी और उन्हें 10 ग्राम सोने पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिला। हालांकि, इस खरीदारी के बदले उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। महिला ने कहा कि सोने की कीमतें बहुत ज्यादा होने के कारण यह ऑफर छोड़ना मुश्किल था और उन्हें ज्वेलर पर भरोसा था।

भारत में सोने पर आयात शुल्क बढ़ने से आधिकारिक चैनल से आने वाले सोने की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा, खुदरा खरीदारों को सोने की



खरीद पर 3% जीएसटी भी देना होता है। ऐसे में कुछ खरीदार अतिरिक्त लागत से बचने के लिए कैश और बिना बिल वाली खरीदारी का विकल्प चुन रहे हैं। भारत के अनौपचारिक कैश मार्केट में सोना घरेलू बाजार की मौजूदा कीमत से 200 डॉलर प्रति औंस तक कम कीमत पर उपलब्ध होने की बात सामने आई है। हालांकि, इस अनौपचारिक बाजार में कीमतें तय नहीं होतीं और ग्राहक तथा डीलर के बीच बातचीत के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा ग्राहक भी ज्वेलर से मोलभाव करके हर 10 ग्राम पर 10000 रुपये तक का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं।

न्यूज ब्रीफ

01 अक्टूबर 2026 को निर्धारित दिव्यांग बोर्ड निरस्त

भिण्ड। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्तपाल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिण्ड ने जिला चिकित्सालय भिण्ड में संचालित दिव्यांगता बोर्ड के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को दिव्यांग बोर्ड विशेषज्ञों की ड्यूटी वृद्ध आश्रम जिला भिण्ड में होने के कारण दिनांक 01 अक्टूबर 2026 का दिव्यांग बोर्ड का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। अतः दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को निर्धारित दिव्यांग बोर्ड को निरस्त किया जाता है। समस्त दिव्यांग आवेदकों से अनुरोध है कि वे उक्त तिथि को उपस्थित न हों।

विशेष ई-केवायसी अभियान 04 अक्टूबर तक

भिण्ड। राज्य सरकार के निदेर्शानुसार जिले में जो भी नवीन पात्रता पचीर्धारी हैं जिनके द्वारा नवीन पात्रता पर्ची बनने हेतु आवेदन राशन मित्र पोर्टल पर किया जा चुका है। ऐसे परिवारों को पीओएस मशीन पर नवीन पात्रता पर्ची हेतु पात्र समस्त परिवार के सदस्यों की एवं पहले से जारी पर्ची में नये सदस्यों को जुडवाने हेतु भी ई-केवायसी पीओएस मशीन पर करवानी होगी। उसके उपरांत ही पात्र नवीन परिवारों एवं नवीन सदस्यों की राशन पर्ची शासन स्तर से जारी कि जा रही है। सभी नवीन पात्रता पचीर्धारियों एवं पहले से जारी पर्ची में नये सदस्यों जिनके द्वारा नवीन पर्ची एवं नये सदस्यों को जोडने हेतु आवेदन किया गया है, उन सभी नागरिकों से अनुरोध है कि दिनांक 04 अक्टूबर 2026 तक विशेष ई-केवायसी अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी हितग्राही अपनी क्षेत्र की नजदीकी राशन दुकान पर जाकर सभी सदस्यों की ई-केवायसी करवाऐं। ई-केवायसी करवाने में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से कार्यालय में जाकर सम्पर्क करें। जिससे की शासन स्तर से पात्रता पर्ची जल्द से जल्द चालू की जा सके। जिससे की आपको प्रतिमाह राशन प्राप्त हो सके।

औषधि निरीक्षक ने तहसील भिण्ड स्थित तीन मेडिकल स्टोरों को किया नोटिस जारी

भिण्ड। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल (म.प्र.), कलेक्टर भिण्ड एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के निदेर्शानुसार औषधि निरीक्षक डॉ आकांक्षा गरुड़ द्वारा विगत दिवसों में तहसील भिण्ड क्षेत्र में स्थित श्री गणेश मेडिकल स्टोर, प्रज्ञा मेडिकल स्टोर, कुशवाह मेडिकल एजेंसी, सेजल मेडिकल स्टोर, अनुष्का मेडिकल स्टोर, काव्या मेडिकल स्टोर एवं आशी मेडिकल स्टोर का औचक निरिक्षण किया गया। आशी मेडिकल स्टोर पर प्रोप्राइटर एवं सक्षम व्यक्ति श्री आलोक शर्मा अनुपस्थित पाए गए तथा उनके स्थान पर दुकान पर श्री अमन सिंह भदौरिया पाए गए। अतः उक्त मेडिकल के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर बंद कराया गया। इस सम्बन्ध में तीन दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दो अन्य मेडिकल स्टोरों श्री गणेश मेडिकल स्टोर एवं प्रज्ञा मेडिकल स्टोर को भी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किये गए हैं। निरीक्षण के दौरान उचित स्थान पर लाइसेंस का प्रदर्शन, दुकानों पर फार्मसिस्ट एवं सक्षम व्यक्ति की उपलब्धता, दुकानों की साफ सफाई, एक्सपाइरी दवाओं के लिए उचित व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर एवं पशुओं के लिए उपयोगी दवाओं को अलग से रखने की व्यवस्था, फ्रिज में संधारित की जाने वाली औषधियों का रख रखाव, बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के शेड्यूल औषधियों का विक्रय नहीं किए जाने एवं औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख का संधारण नियमानुसार रखने संबंधी दिशा निर्देश दिए।



महिला ट्रैप व्यक्तिगत के बाद मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण, नीरू ने जीता तीसरा पदक

एशियन गेम्स में नीरू ढांडा का दूसरा गोल्ड, मिक्स्ड टीम में भी रचा इतिहास

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

एशियन गेम्स 2026 में मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी नीरू ढांडा ने एक और स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की है। 30 सितंबर को ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में नीरू ढांडा और क्यानन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स में अपना तीसरा पदक और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है।

नीरू ने इससे पहले महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। वहीं महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में उन्होंने मनीषा कीर और आशिमा अहलावत के साथ भारत को रजत पदक दिलाया था। अब मिक्स्ड टीम में स्वर्ण जीतकर उन्होंने एशियन गेम्स में अपने पदकों की संख्या तीन कर ली है।

मिक्स्ड टीम में नीरू-क्यानन की जोड़ी का गोल्डन निशाना

ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में नीरू ढांडा और क्यानन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इस स्वर्ण के साथ नीरू के एशियन गेम्स 2026 अभियान में अब दो स्वर्ण और एक रजत पदक हो गए हैं।



महिला ट्रैप व्यक्तिगत में भी जीता था ऐतिहासिक स्वर्ण

29 सितंबर को नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। उनके प्रदर्शन ने नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। वह एशियन गेम्स में महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं।

इसी दिन महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ने भारत को रजत पदक दिलाया था। नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत की भारतीय टीम ने 328 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। टीम की ओर से नीरू ने 118, आशिमा ने 106 और मनीषा ने 104 अंक अर्जित किए।

मध्यप्रदेश के खाते में अब 8 पदक

नीरू ढांडा के मिक्स्ड टीम स्वर्ण के साथ एशियन गेम्स 2026 में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के पदकों की संख्या 8 हो गई है। प्रदेश ने अब तक 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है।

नीरू के नाम तीन पदक, दो स्वर्ण

एशियन गेम्स में नीरू ढांडा का प्रदर्शन मध्यप्रदेश के लिए खास उपलब्धि बन गया है। उन्होंने महिला ट्रैप व्यक्तिगत में स्वर्ण, महिला ट्रैप टीम में रजत और अब ट्रैप मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीतकर तीन पदक अपने नाम किए हैं। इनमें दो स्वर्ण पदक शामिल हैं।

मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन

नीरू ढांडा और मनीषा कीर का प्रदर्शन मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को भी सामने लाता है। भोपाल स्थित अकादमी में खिलाड़ियों को शॉटगन सहित शूटिंग की आधुनिक सुविधाओं और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।

एक बस में 80 90 बच्चों को बैठाने का आरोप परिवहन व्यवस्था सुधारने की मांग



एक सत बुलेटिन, बैरसिया

संदीपनी सीएम राइज स्कूल बैरसिया में परिवहन व्यवस्था को लेकर बुधवार को छात्रों का आक्रोश सामने आया है जहां विद्यालय में बसों की कमी और क्षमता से अधिक बच्चों को बसों में बैठाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल के सामने चक्का जाम कर दिया। छात्रों ने बसों की संख्या बढ़ाने और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि एक बस में करीब 80 से 90 बच्चों को बैठाकर सफर कराया जा रहा है। इससे उन्हें सफर के दौरान काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि क्षमता से अधिक बच्चों के परिवहन से असुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता बनी रहती है गौरतलब है कि चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद अधिकारी और स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचे। अधिकारियों एवं स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और परिवहन व्यवस्था में सुधार का आश्वासन देते हुए समाधान का प्रयास किया। छात्रों ने बसों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने की मांग की।

बिजली उपभोक्ताओं को अलर्ट

फर्जी मैसेज और कॉल के जरिए हो रही ठगी बिल भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से करें

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के सम्माननीय बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का नगद भुगतान कंपनी के जोन, वितरण केन्द्र कार्यालय, पीओएस मशीन अथवा अधिकृत भुगतान केन्द्रों जैसे एम.पी.ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर पर ही करें। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के केशलेस भुगतान हेतु कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम एप, व्हाट्सएप पे एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से भी बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि उपभोक्ता को असमय विद्युत विच्छेदन से बचने हेतु किसी निजी मोबाईल नंबर से कॉल कर भुगतान करने हेतु कोई एसएमएस/ व्हाट्सएप जारी नहीं किया जाता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एसएमएस केवल सीसीएमपीसीजेड एवं व्हाट्सएप केवल 07552551222 सेंडर आईडी से ही प्रेषित किए जाते हैं। उपभोक्ता किसी अन्य सेंडर आईडी अथवा निजी नंबर से आए भ्रामक मेसेज से सतर्क रहें। कंपनी अंतर्गत विद्युत देयकों के भुगतान के लिए उपभोक्ता पहचान नंबर यानि आईवीआरएस नंबर की जरूरत होती है। आईवीआरएस नंबर के आधार पर ही जोन, वितरण केन्द्रों या अन्य गेटवे एमपी ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे. अमेजन पे, व्हाट्सएप पे आदि पर बिजली बिलों का भुगतान होता है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से आए फोन या व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर किसी भी मोबाइल नंबर पर देयकों की राशि अंतरित न करें। साथ ही अपना पिन नंबर भी किसी के साथ साझा न करें।

कंपनी के संज्ञान में आया है कि सायबर जालसाजों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज अथवा आई.व्ही.आर. तकनीक से फोन कॉल पर नंबर दबाने हेतु कहा जाता है जिसमें बिल भुगतान कराने हेतु भय बनाकर कि आपकी बिजली कुछ घंटों बाद काट दी जाएगी, इसके लिए बिल भुगतान करने हेतु विशेष नंबर दबाएं, मोबाइल नंबर विशेष अथवा अनजान लिंक/एप पर क्लिक कर या संपर्क कर बकाया राशि जमा कराएं। इस प्रकार के एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज एवं आई.व्ही.आर. फोन कॉल फर्जी हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जाए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है इस प्रकार के फर्जी सायबर जालसाजों से सतर्क और सावधान रहें। साइबर फ्रॉड संबंधित किसी भी घटना की सूचना तत्काल भारत सरकार की हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराए।

यदि किसी अनजान नंबर से बिजली संबंधी कार्य के लिए फोन आता है, तो उपभोक्ता संबंधित व्यक्ति से उसका Employee ID अवश्य पूछें। इसके बाद वढअ अस्त्रस्त्र के होम पेज पर नीचे स्क्रॉल कर "Other Services" में उपलब्ध Employee VerificÔtion" विकल्प पर जाकर Employee ID दर्ज करें और संबंधित व्यक्ति का सत्यापन करें।

जमीन संबंधी मामलों में मिल रही तारीख पर तारीख

जमीन संबंधी मामलों में मिल रही तारीख पर तारीख

एक सत बुलेटिन, **बैरसिया**

तहसील कार्यालय में जमीन संबंधी कार्यों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ओर किसानों का आरोप है कि तहसील कार्यालय में बाबू की दलाल और बिचौलिया से साठगांठ के चलते समय पर राजस्व प्रकरणों सहित सीमांकन,नामांकन ओर नकल आदि के प्रकरण बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े हैं। ओर जिम्मेदार अधिकारी सर्किल तहसीलदारो का भी किसानों की इस समस्या की ओर ध्यान नही है ओर बाबू तहसीलदार कोट के प्रकरणों में बार-बार तारीख पर तारीख दे रहे हैं।

तारीख पर तारीख से बढ़ रही छोटे किसानों की परेशानी

किसानों का कहना है कि उनके भूमि,भवन संबंधी कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं,बाबू उन्हें हर बार अगली तारीख बताकर बगैर निराकरण के घर वापिस लौटा रहे हैं। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहा है।



वरिष्ठ अधिकारियों से जांच और पारदर्शी व्यवस्था की मांग।

क्षेत्र के किसान खासकर महिला किसानों ने एसडीएम और तहसीलदार से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय में दलालों एवं बिचौलियों की सक्रियता पर रोक लगाने के साथ किसानों के राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में संतुष्टि पूर्वक निराकरण एव सुनवाई पारदर्शी कार्यप्रणाली अनुसार सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

इन मामलों से संबंधित जानकारी लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने कॉल रिसीवड नहीं किया

दलालों की कथित सक्रियता पर उठ रहे सवाल

तहसील कार्यालय में कथित रूप से बर्षो से जमे तहसीलदार के बाबू सुभवः बागड़े की साठगांठ दलालों और बिचौलियों से होने के कारण किसानों के प्रकरणों की फाइलें तक गायब हो जाने की शिकायतें तहसीलदार ओर एसडीएम से किसानों के साथ अधिवक्ताओं ने लिखित में तक दे दी है। फिर भी व्यवस्था में कोई सुधार नही हुआ इससे ग्रामीणों ओर किसानों में गहरी नाराजगी है।

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का हुआ आयोजन

भिण्ड। सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन आज परियोजना गोहद, मौ एवं लहार में किया गया। ऑगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत परियोजना अंतर्गत ऑगनबाडी केन्द्रों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। क्षेत्र अंतर्गत लाभार्थी बच्चे एवं उनके परिजन तथा सामान्य जन समुदाय उपस्थित रहे।

आज के कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा पौधारोपण कराया गया एवं पेड़-पौधों के संबंध जागरूकता की जानकारी से अवगत कराया गया, बच्चों के द्वारा पेंटिंग करवाई गई। पौधारोपण कार्यक्रम कराया गया तथा बच्चों के द्वारा कहानी कविताऐं सुनाई गई। आंगन मिलन सेवा संदेश का वाचन कराया गया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान: भोपाल मंडल के स्टेशनों पर पेयजल गुणवत्ता की सघन जांच, 144 परीक्षण, सभी परिणाम संतोषजनक

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीआरएम श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 28 से 30 सितम्बर 2026 तक विशेष वॉटर सैनिटेशन ड्राइव चलाया गया। इस दौरान मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों एवं रेल परिसरों में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता की सघन निगरानी करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप जल नमूनों की जांच की गई।





अभियान के दौरान पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुल 144 परीक्षण किए गए। इनमें 125 क्लोरीन परीक्षण, 18 जीवाणु परीक्षण तथा 01 रासायनिक परीक्षण शामिल हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से पेयजल में क्लोरीन की मात्रा, जीवाणु संबंधी मानकों तथा रासायनिक गुणवत्ता की जांच की गई। सभी जांचे गए जल नमूनों के परीक्षण परिणाम संतोषजनक पाए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जांच किए गए पेयजल स्रोत निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

भोपाल मंडल द्वारा यात्रियों एवं रेल परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्रोतों की नियमित निगरानी तथा समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित इस विशेष ड्राइव के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा दिया गया। सीनियर डीसीएम श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें तथा रेलवे परिसर को स्वच्छ एवं स्वच्छतापूर्ण बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें।

मुख्य सचिव श्री बर्णवाल से मिलीं बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ. शर्मा

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल से मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने बुधवार को भेंट कर प्रदेश में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण और विद्यालयों में बच्चों के लिए बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

स्कूलों में शौचालय और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से लेकर बालिका गरिमा सूचकांक के विषय पर की बात

डॉ. शर्मा ने मुख्य सचिव के समक्ष विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, बालिका गरिमा सूचकांक, स्पॉन्सरशिप तथा बाल संरक्षण से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की गरिमा, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी समन्वय जरूरी है।

बैठक में आयोग द्वारा प्रदेश स्तर पर बच्चों की शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर आयोजित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। ऐसे शिविरों के माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुनकर उनके त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई किए जाने पर विचार किया गया।

आयोग की अध्यक्ष ने बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर शासन और आयोग के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर भी चर्चा की। बैठक में बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल वातावरण विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं विनर प्रिंटर्स, सिविक सेंटर, तीन बत्ती चौराहा, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादक: विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें– ए–1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755–4515227, मोबाइल: 9893111784